राजस्थान समसामयिकी

राजस्थान अंशकालिक श्रमिकों हेतु न्यूनतम मजदूरी लागू करने वाला पहला राज्य बना

- अंशकालिक श्रमिकों हेतु न्यूनतम मजदूरी लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है. राज्य के श्रम विभाग ने 06 जुलाई 2016 को इस सिलसिले में अधिसूचना भी जारी कर दी है.

अधिसूचना से अंशकालिक श्रमिकों को होने वाले लाभ-

- अधिसूचना के अनुसार जो भी श्रमिक एक दिन में चार घंटे से कम काम करेगा, उसे न्यूनतम मजदूरी की पचास प्रतिशत राशि दी जाएगी.
- इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही अंशकालिक श्रमिक न्यूनतम वेतन कानून 1948 के तहत लाभान्वित होने लगेंगे.
- एक अन्य फैसले में सरकार ने सभी वर्गों में न्यूनतम वेतन राशि में 104 रूपये प्रतिमाह की वृद्धि कर दी है.
- राजस्थान सरकार के 51 क्षेत्रों में कार्यरत लाखों श्रमिकों को लाभ मिलेगा.
- अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में मजदूरी दर अब काफी अधिक हो गई है.
- न्यूनतम मजदूरी दरों में इजाफे का लाभ प्रदेश के कारोबार उद्यम को भी मिलेगा.

राज वायु मोबाइल ऐप

- राजस्थान सरकार ने 5 जून 2016 को प्रदेश के तीन शहरों जयपुर, जोधपुर और उदयपुर की हवा में प्रदूषण के स्तर की जानकारी और चेतावनी देने हेतु मोबाइल एप राजवायु लॉन्च किया. एप्लिकेशन राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर लॉन्च किया.
- राजस्थान ऐसा पहला राज्य है, जिसने राज्य स्तर पर यह एप लॉन्च किया है. इस एप पर प्रदूषण और मौसम के अनुरूप चेतावनी और हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की जाएगी. इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है.

राज वायु ऐप की मुख्य विशेषताएं-

- राज वायु एप्लिकेशन पर उपलब्ध कराई गई सूचना परिष्कृत हवा की गुणवत्ता की निगरानी उपकरण और मौसम सेंसर द्वारा एकत्र आंकड़ों पर आधारित है.
- अनुप्रयोग को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (आरएसपीसीबी)/ (RSPCB) भारतीय मौसम विज्ञान के उष्णकटिबंधीय संस्थान से (आईआईटीएम) ने संयुक्त रूप से डिजाइन किया है.
- यह एप रिहायशी और पर्यटन स्थलों पर हवा की गुणवत्ता और प्रदूषण स्तर के बारे में ओक्साइड्स ऑफ़ सल्फर, नाइट्रोजन (SOx), (NOx), कार्बन मोनो ओक्साइड, ओजोन कणों और पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) की जानकारी उपलब्ध कराएगा.
- यह तापमान, हवा की गति, आर्द्रता, मौसम पूर्वानुमान और परामर्श भी उपलब्ध कराएगा.
- यह एप्लिकेशन वायु गुणवत्ता और मौसम के पूर्वानुमान की प्रणाली रिसर्च (सफ़र-भारत) / (SAFAR-India) पर आधारित है. जो वर्तमान में दिल्ली, मुंबई और पुणे से जुड़ा हुआ है.
- 2017 तक इसकी सेवाओं का अजमेर, अलवर, भिवाड़ी, कोटा और पाली में सहित राज्य के अन्य शहरों में विस्तार किया जाएगा.

प्रोजेक्ट डायरेक्टर के बारे में-

- इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वैज्ञानिक गुफरान बेग मूलत: उदयपुर के ही रहने वाले हैं.
- उदयपुर शहर के प्रदूषण के साथ ही तापमान, आर्द्रता और वायु की दिशा की जानकारी भी मिल पाएगी.
- इससे पहले दिल्ली, मुंबई और पुणे शहर के लिए इस तरह के एप लॉन्च किए गए.

राजस्थान शहरी भूमि (सर्टिफिकेशन ऑफ टाइटिल्स) विधेयक 2016

- अप्रैल 2016 के पहले सप्ताह में राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान शहरी भूमि (सर्टिफिकेशन ऑफ टाइटिल्स) विधेयक 2016 पारित कर दिया. इसके साथ ही राजस्थान लैंड टाइटिल बिल लाने और पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है.
- विधेयक जो मालिक को स्पष्ट टाइटिल देगा और अदालतों में मुकदमों की संख्या कम हो जाएगी,को ध्वनिमत से पारित किया गया. इस विधेयक का उद्देश्य मामूली शुल्क लेकर स्वामित्व का प्रमाणपत्र जारी कर शहरी इलाकों में गैर– कृषि भूमि की खरीद और बिक्री में होने वाली धोखाधड़ी के मामलों को कम करना है.

विधेयक की विशेषताएं

- नगरपालिकाओं या राज्य विकास प्राधिकरणों द्वारा शासित शहरी क्षेत्रों में रहने वाले राज्य के निवासी राज्य सरकार को मामूली शुल्क का भुगतान कर अपने जमीन पर स्वामित्व का प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं.
- राज्य सरकार एक प्राधिकरण बनाएगी जिसका मुखिया भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा.
- यह जमीन के मालिकों से सभी दस्तावेज प्राप्त करेगा और राज्य के रिकॉर्ड से इसकी सत्यापन करेगा.
- अधिकारी पहले अस्थायी प्रमाणपत्र जारी करेगा, जिसकी गारंटी राज्य सरकार नहीं लेगी. अगर इस पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति या विवाद पैदा नहीं होता है तब अधिकारी राज्य की गारंटी के साथ एक प्रमाणपत्र और मानचित्र मालिक को जारी करेगा.

राजस्थान बजट 2016-17

राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 8 मार्च 2016 को राज्य का वर्ष 2016-17 का बजट विधान सभा में पेश किया.

संबंधित मुख्य तथ्य:

- वर्ष 2016-17 के बजट में कुल राजस्व आय 123250 करोड रुपए का अनुमान
- राजस्व घाटा 8800 करोड़ रहने का अनुमान
- लीज दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी खत्म
- करों में करीब 325 करोड़ की राहत
- फूड प्रोसेसिंग पार्क के लिए अतिरिक्त रियायत
- भू रूपांतरण की छूट 50 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी
- लग्जरी टैक्स में संशोधन का प्रस्ताव, आयातित माल पर 5.5 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव
- ई ट्रांजिक्ट पास दिए जाएंगे
- ई कॉमर्स पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नियमों में संशोधन, 5-5 की दर से कर आरोपित
- 5000 छोटे डीलर्स को डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा

- 10 लाख के एजुकेशन लोन पर स्टांप ड्यूटी समाप्त, संपत्ति के रजिस्ट्रेशन में छूटपुलिस आधुनिकीकरण के लिए 134 करोड़
- स्मार्ट सिटी के लिए 400 करोड़ का प्रावधान, सीवरेज परियोजना के लिए 73 करोड़
- शमशानों और कब्रिस्तानों के विकास के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
- अजमेर में 4 करोड़ की लागत से बनेंगे 4 ऑपरेशन थिएटर
- भामाशाह योजना एक्ट की घोषणा
- बैंकों की 500 नई शाखाए खुलेंगी
- 40 गांवों की सहभागिता से मिनी बैंक काम करेंगे
- ग्रामीण विकास और पंचायतीराज के लिए 15 हजार 378 करोड़ का प्रावधान
- पंचायतीराज संस्थाओं को मजबूत और पारदर्शी बनाया जाएगा
- नगरीय विकास के लिए 6 हजार 642 करोड़ का प्रावधान
- प्रदेश के 37 शहरों में जल वितरण और सीवरेज से जुड़े कार्य हेतु 4200 करोड़ रुपए का प्रावधआन
- स्कूली शिक्षा के लिए 23 हजार 177 करोड़ का प्रावधान
- आईटीआई के लिए 213 करोड़ रुपए का बजट
- ग्रीन हाउस पर सब्सिडी बढ़कर 70 फीसदी
- राजस्थान में भंडारण क्षमता के विकास के लिए 162 करोड़ रुपए
- 12,000 करोड़ की लागत से सिंचाई व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा
- इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए 377 करोड़
- पशु चिकित्सा के क्षेत्र में पढ़ रहे छात्रों को 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी
- फसल बीमा योजना के लिए 676 करोड़, ई मंडी की स्थापना होगी
- पर्यटन विकास के लिए 62 करोड़ 16 लाख रुपए
- हवाई पट्टियों के विकास के लिए 17 करोड़ 80 लाख
- 13 लंबित परियोजनाओं के लिए 831 करोड़ रुपए

खेल

- एसएमएस स्टेडियम में खिलाड़ियों के ठहरने के लिए खेल भवन का निर्माण
- प्रतियोगिता भी आयेाजित की जाएगी 14 खेलों के लिए खेल प्रतिभा खोजने प्रतियोगिता होगी। -इसमें 10वीं से 12वीं तक के खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा
- राज्य व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वालों को कई विभागों में नियुक्ति देने की घोषणा
- खींवसर जिला नागौर में इंडोर वॉल का निर्माण कराया जाएगा
- कई स्टेडियमों के लिए 17 करोड़ रुपए का प्रावधान
- खेल अकादमी की स्थापना के लिए योजना बनाई जाएगी
- हर साल कक्षा 8 से 12 तक की छात्राओं के लिए योजना
- कबडडी व हॉकी के लिए एक एक राज्यस्तरीय टीम को रीको व आरएसएमएस स्पॉंसर करेगी

शिक्षा

- राज्य सरकार की ओर से स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल जैसी योजनाओं के लिए 23 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान
- नए मॉडल स्कूलों का निर्माण किया जाएगा. कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल संचालित होंगे.
- मार्च 2016 तक 6 और बालिका छात्रावासों का निर्माण कराया जाएगा
- 290 के अलावा 380 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा
- प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए 180 करोड़ रुपए की लागत से 1600 से अधिक कक्षा कक्ष, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम का निर्माण कराया जाएगा
- राज्य में 60 भवनों का निर्माण जर्जर भवनो वाली स्कूलों के लिए कराया जाएगा
- आठवीं, 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा के टॉपर्स को लेपटॉप वितरण किया जाएगा. साइकिल वितरण के लिए 85 करोड़ रुपए का प्रावधान
- 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर पढ़ने जाने वाली बालिकाओं को ट्रांसफर बाउचर्स का लाभ दिया जाएगा
- संस्कृत भाषा के महापुरा जयपुर स्कूल को क्रमोन्नत किया जाएगा प्रशिक्षण के लिए
- कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए 175 करोड़ की ग्रांट का प्रावधान
- खाजूवाला बीकानेर, करणपुर, रावतभाटा, खचिड़ावा, खींवसर व बड़ी सादड़ी में नए को-एड कॉलेज
- कई कॉलेजों में नए विषयों की कक्षाओं के खोले जोन का प्रावधान
- सीकर व झालावाड़ समेत कई जिलों में कॉलेजों में वाईफाई सुविधा

स्वास्थ्य सेवा

- कई स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में बैड बढ़ाए जाएंगे
- मेडिकल संस्थाओं में नई डेंटल सुविधाओं का प्रावधान

रोजगार

- राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड का भवन बनाया जाएगा
- 7वें वेतनमान के केंद्र आदेश जारी करने के बाद रिवाइज वेतन के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी.
- सभी राज्य बीमा व जीपीएफ के ऋण संबंधी मामलों में लिए ई-पोर्टल बनाया जाएगा.
- सरकारी कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की राशि 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए.

सूचना एंव जनसंपर्क

- जैसलमेर व चित्तौडगढ में नए सूचना केंद्र की घोषणा
- नीमराणा, चूरू, मूंडवा में उपकोष कार्यालय

विधि एवं न्याय

- मालाखेड़ अलवर, जमवारामगढ़ जयपुर, बीकानेर में एक पारिवारिक न्यायालय, फतहपुर व खैरवाडा में अधीनस्थ न्यायालय खुलेंगे.

राजस्व सैनिक कल्याण

- राजस्व भवनों के विकास के लिए 163 करोड़ रुपए का प्रस्ताव. आधारभूत सुविधाओं के लिए भी राशि
- ई-धरती कार्यक्रम के तहत नक्शों को ऑनलाइन किया जाएंगा
- भू-प्रबंध अधिकारी कार्यालय में जीआईएस लैब की स्थापना होगी. सैनिक विश्राम गृह उदयपुर का अपग्रेडेटेशन
- सर्वात्तम युद्ध सेवा मेडल को 16 लाख रुपए देने की घोषणा.

बाड़मेर में स्वच्छ पीने के पानी के लिए राजस्थान सरकार ने केयर्न इंडिया के साथ समझौता किया

- राजस्थान सरकार ने 7 जनवरी 2016 को बाड़मेर में स्वच्छ पीने के पानी के लिए केयर्न इंडिया के साथ समझौता किया है. पीने का पानी थार रेगिस्तान में एक बहुमूल्य वस्तु है. समझौते के बाद प्रदेश में बाड़मेर ज़िले के लोगों को आरओ प्लांट से साफ़ सुथरा पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा.
- इस करार के तहत केयर्न इंडिया बाड़मेर में आने वाले तीन सालों में 333 आरओ प्लांट (क्षमता प्रति 1,000-3,000 लीटर प्रति घंटा) लगाएगी.

- इस एमओयू पर राजस्थान सरकार के जलदाय विभाग और केयर्न इंडिया के बीच हस्ताक्षर किए गए.
- जलदाय विभाग की ओर से मुख्य अभियंता ग्रामीण अखिल कुमार जैन और केयर्न की ओर से सिद्धार्थ बालाकृष्णन ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए.
- बड़ी संख्या में आरओ प्लांट लग जाने के बाद बाड़मेर ज़िले के 800 से भी ज़्यादा गांवों को पीने का साफ़ पानी मिल सकेगा. जिसमे एक लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित होने का अनुमान है
- इन जल परियोजनाओं को आस-पास के गांवों तक अधिकतम सुविधाजनक तरीके से स्थापित किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को इस सुविधा के लिए अधिक दूर तक न जाना पड़े.
- वितरण को सुगम बनाने के लिए कई स्थानों पर वाटर एटीएम भी लगाए जाएंगे.
- इन प्लांट्स की स्थापना का खर्च केयर्न इंडिया से जुड़ा केयर्न एंटरप्राइज सेंटर वहन करेगा.
- जबकि जलदाय विभाग भूमि, जल स्त्रोत और विद्युत उपलब्धता में ग्राम पंचायत की सहायता से सहयोग करेगा.
- प्रोजेक्ट के तहत वाटर एटीएम कियोस्क की स्थापना गांवों में ऐसे स्थानों पर की जाएगी, जहां ग्रामीण आसानी से पहुंच सकें. ये जल कियोस्क ग्राम जल समिति द्वारा संचालित किए जाएंगे.
- आरओ प्लांट से स्वच्छ पानी के लिए ग्रामीणों को न्यूनतम भुगतान करना होगा.

केयर्न इंडिया के बारे में-

- केयर्न इंडिया तेल और गैस की खोज कंपनी द्वारा समर्थित संस्था है.
- बाड़मेर जिले में केयर्न इंडिया की तेल क्षेत्र की प्रमुख कंपनी प्रति दिन 175,000 से अधिक बैरल तेल का उत्पादन करती है.
- केयर्न इंडिया ने रिवर्स ऑस्मोसिस सुविधाओं की स्थापना के माध्यम से बाड़मेर और जालौर में लोगों को स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित कराने के लिए राज्य सरकार के सहयोग से 2014 में 'जीवन अमृत "पायलट परियोजना शुरू की थी.

राजस्थान में 126 मेगावाट की प्रतापगढ़ पवन परियोजना की शुरुआत

- ऊर्जा उत्पादन कंपनी वेलस्पन रिन्यूवल एनर्जी ने 7 दिसम्बर 2015 को राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में 126 मेगावाट पवन परियोजना के शुरू करने की घोषणा की. यह 126 मेगावाट प्रतापगढ़ पवन परियोजना वेलस्पन रिन्यूवल एनर्जी पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी पवन परियोजना है.
- यह परियोजना 290 मिलियन यूनिट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करेगी और वार्षिक 211922 टन कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी. कंपनी ने इस परियोजना में 840 करोड़ रुपए का निवेश किया है.
- विदित हो वर्ष 2015 में वेलस्पन रिन्यूवल एनर्जी ने पूरे देश में 700 मेगावाट (डीसी) ऊर्जा का उत्पादन किया है.
- कम्पनी का लक्ष्य इस वित्त वर्ष में 1 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा(सौर्य और पवन ऊर्जा के माध्यम से) का उत्पादन है. वर्तमान में वेलस्पन रिन्यूवल एनर्जी भारत के 10 राज्यों में में मौजूद है.
- वेलस्पन एनर्जी लिमिटेड एक स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादनकर्ता कंपनी है. यह नई दिल्ली, भारत में स्थित है. यह भारत की सबसे बड़ी सौर्य ऊर्जा उताप्दन कम्पनी है. विदित हो इस कम्पनी के कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन(यूएनएफसीसी) में पंजीकृत है.
- ज्ञात हो वर्ष 2014 के 31 दिसम्बर तक नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन भारत में 33.8 गीगावाट थी.

राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण और कृषि-विपणन संवर्धन नीति 2015

- राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 5 नवंबर 2015 को कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देने और फसल में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए राजस्थान कृषि प्रसंस्करण और कृषि-विपणन संवर्धन नीति 2015 का शुभारंभ किया.
- राजस्थान सरकार का कृषि विभाग नीति के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड नीति के लिए नोडल एजेंसी होगा.
- नीति का उद्देश्य किसान को कृषि उपज का अधिकतम मूल्य दिलवाना है. राज्य सरकार ने नीति के शुभारंभ के समय विभिन्न क्षेत्रों में निजी कंपनियों के साथ 112 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए.

कृषि प्रसंस्करण और 2015 कृषि विपणन संवर्धन नीति के प्रावधान

- राजस्थान कृषि प्रसंस्करण और कृषि-विपणन सामान्य प्रावधानों की तुलना में अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 के तहत शामिल किया गया है.
- इसके अलावा पेटेंट उत्पादों पर अतिरिक्त प्रोत्साहन, उत्पाद पंजीकरण, गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए सब्सिडी का प्रावधान, विदेशों में नमूने भेजना, परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, फल, सब्जियों और मसालों को विदेश भेजने के लिए परिवहन उपलब्ध करानाहोगा आदि शामिल है.
- निवेशक कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में 25 लाख रुपये से अधिक का निवेश करेंगे. निवेशकों को 60 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी. इससे 10 प्रतिशत रोजगार का सृजन होगा.
- इन निवेशकों को भूमि कर, बिजली शुल्क और मंडी कर, स्टांप शुल्क, रूपांतरण शुल्क और एंट्री टैक्स राज्य में संयंत्र और मशीनरी और 7 साल तक उपकर में 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी.
- मवेशी फीड और पोल्ट्री फीड निर्माण इकाइयों को 5 साल की अवधि के ऋण पर या ऋण समाप्ति तक जो भी पहले जमा किया जाता है पर 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाएगी.
- ऐसे उद्यमी को जो एक ही उद्यम में 250 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन करेगा या खेती सम्बन्धी विशिष्ट उत्पाद इकाई को 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रदान किया जाएगा.
- फूड पार्क के लिए भूमि हस्तांतरण पर पहली बार स्टांप शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट में प्रदान की जाएगी.

राजस्थान के जालौर में अंतर्देशीय शिपिंग बंदरगाह

- शिपिंग मंत्रालय के अधीनस्थ भारतीय अंतर्देशीय जलामार्ग प्राधिकरण ने 4 नवम्बर 2015 को जालौर में एक अंतर्देशीय शिपिंग बंदरगाह के निर्माण के लिए राजस्थान सरकार का मार्गदर्शन एवं सहायता करने का प्रस्ताव रखा. यहां विकसित किए जाने वाले बंदरगाह एवं टर्मिनल से पश्चिमी राजस्थान में अंतर्देशीय नौवहन सुविधाओं के विकास में मदद मिलेगी. यही नहीं, इससे इस क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास भी संभव हो पाएगा. राज्य सरकार नहर के आसपास चूना पत्थर, जिप्सम, लिग्नाइट और सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए व्यावसायिक विकास अवसरों की तलाश करेगी.
- इस परियोजना की संभाव्यता-पूर्व रिपोर्ट को तैयार करने का काम वैप्कॉस द्वारा किया जाएगा. इसकी ओर से रिपोर्ट पांच माह के भीतर पेश कर दी जाएगी. इस दौरान भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इस पर पूरी तरह से नजर रखेगा और इसके साथ ही वह इसके लिए मार्गदर्शन भी करेगा.

- इसके अतिरिक्त मोरी खाड़ी और जालौर के बीच एक नहर बनाने का प्रस्ताव है. इस नहर को तीन मीटर की न्यूनतम तलछट को बरकरार रखना होगा.
  यहां स्थित जल को लवण मुक्त करने और सिंचाई के लिए इसका उपयोग करने के प्रयास किए जाएंगे. इससे सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास और इस क्षेत्र में कृषि पैटर्न को बेहतर करने में मदद मिलेगी. नहर के आसपास कृषि से जुड़ी विविधता में बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए लवण प्रतिरोधी फसलों जैसे सोया की लाभप्रदता का भी अध्ययन किया जाएगा.
- इसके अलावा इस खण्ड में स्मार्ट सिटीज का विकास करने की भी योजना है. इसी तरह इंदिरा गांधी नहर को जहाजों के चलने योग्य बनाने के उद्देश्य से भी अध्ययन कराया जाएगा.

राजस्थान पर्यटन इकाई नीति-2015

- इस नीति में पर्यटन क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जिनमें अब होटल, मोटेल, हैरिटेज होटल, बजट होटल, रेस्टोरेन्ट, केम्पिंग साइट, माइसध्कनवेन्शन सेन्टर, स्पोट्र्स रिसोर्ट, रिसोर्ट, हैल्थ रिसोर्ट, एम्यूजमेन्ट पार्क, एनिमल सफारी पार्क, रोप वे, ट्यूरिस्ट लग्जरी कोच, केरावेन एवं क्रूज पर्यटन समिलित है.
- नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन पर्यटन इकाइयों का भूमि सम्परिवर्तन निरूशुल्क होगा. इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में नई पर्यटन इकाइयों से विकास शुल्क नहीं लिया जायेगा.
- नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान हैरिटेज सम्पत्तियों एवं हैरिटेज होटलों को भू-सम्परिवर्तन शुल्क से मुक्त किया गया है.
- भू-सम्परिवर्तन के लिये समय सीमा निर्धारित की गई है एवं यदि कोई भी प्राधिकरण निर्धारित समय में निर्णय करने में विफल रहता है तो, भूमि को स्वत ही भू-सम्परिवर्तित मान लिया जायेगा.
- हैरिटेज होटलों के आच्छादित क्षेत्र पर नगरीय विकास कर आवासीय दर से वसूल किया जायेगा किन्तु उनके खुले क्षेत्र पर नगरीय विकास कर नहीं लिया जायेगा.
- हैरिटेज होटल के लिए बी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड केवल सकल निर्मित क्षेत्रफल पर देय होगा.
- हैरिटेज होटलों को पट्टा जारी करने के लिये पात्र माना जाएगा.
- नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हैरिटेज होटलों के लिए सड़क की चैड़ाई की कोई बाध्यता नहीं होगी.
- हेरिटेज होटलों एवं पुरासम्पत्तियों के आच्छादित क्षेत्रफल का अधिकतम 10 प्रतिशत अथवा 1000 वर्ग मीटर जो भी कम हो में खुदरा वाणिज्यिक उपयोग स्वतरू अनुज्ञेय होगा.
- भवन योजना का अनुमोदन संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा में किया जायेगा.
- पर्यटन इकाइयों को दोगुना अर्थात् 2.25 से 4.50 एफ.ए.आर. अनुज्ञेय होगा.
- सभी पर्यटन इकाइयां अपने लिए मानव संसाधन प्रशिक्षित करने हेतु राजस्थान कौशल एवं आजिविका विकास निगम के अन्तर्गत रोजगार से जुड़े कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण संस्थानों के अनुमोदन के लिए पात्र होंगी.
- पर्यटन इकाई हेतु सम्परिवर्तित एवं आवंटित भूमि की लीज राशि संस्थानिक प्रयोजनार्थ निर्धारित आरक्षित दर के आधार पर ली जायेगी.
- मान्यता प्राप्त टूर ऑपरेटर के ट्यूरिस्ट लग्जरी कोचेज को स्पेशल रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट अप्रेल 2018 तक प्रदान की जायेगी
- पर्यटन इकाइयों एवं हैरिटेज होटलों को समस्त आर्थिक लाभ राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014 के अन्तर्गत देय होंगे.

खनिज नीति-2015

राजस्थान सरकार ने 5 जून 2015 को खनिज नीति-2015 जारी किया. राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दिल्ली में आयोजित एंबेसडसर राउंड टेबल कांफ्रेंस में 'खनिज नीति-2015' जारी की. खनिज नीति-2015 में अवैध खनन पर सजा 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष तथा जुर्माना 25 हजार रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की गई. इसके साथ ही अवैध खनन करने वालों से 15 गुना रायल्टी वसूली के प्रावधान नई नीति में किए गए. 'खनिज नीति-2015' के तहत खनन से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए सेटलमेंट कमेटी गठित करने का प्रावधान किया गया.

प्रमुख बिन्दु:

- खनिज क्षेत्रों में अन्तरराष्ट्रीय कंपनियों से सर्वे.
- रासायनिक प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण.
- स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन.
- नागुरडा लिग्नाइट ब्लॉक में अंडरग्राउंड कोल गैसीफिकेशन के लिए नेयवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन से ज्वाइन्ट वेन्चर होगा.
- वन क्षेत्र में निजी आवेदकों द्वारा भूमि अनारक्षण करा खान प्राप्त की जा सकेगी.
- टेंडर या नीलामी **या लॉटरी मिलेंगे खनन पट्टे.**
- **प्रधान से अप्रधान** घोषित 31 खनिजों के खनन पट्टे न्यूनतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र के एवं खनिज बजरी के खनन पट्टे 5 से 50 हेक्टे. क्षेत्र के दिये जायेंगे.
- खनिज सैंड स्टोन के खनन पट्टे खातेदारी भूमि में न्यूनतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र के दिए जायेंगे.
- क्वारी लाइसेंस की अवधि 30 साल तथा खनन पट्टों की अवधि 50 साल की जायेगी.

राजस्थान सरकार द्वारा कुपोषण का मुकाबला करने हेतु यूनिसेफ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर

- राजस्थान सरकार ने 4 मई 2015 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), यूनिसेफ तथा गेन (ग्लोबल अलाएंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रीशियन) के साथ जयपुर में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये.
- शुरुआत में इस कार्यक्रम को तेरह जिलों में लागू किया जायेगा जहां 10,000 से अधिक बच्चों में कुपोषण की पहचान की गयी है.

गौ-मूत्र रिफाइनरी

- 3 मई 2015 को राजस्थान के जालौर जिले में स्थित पथमेडा गांव में गौ-उत्पादों पर अनुसंधान हेतु गौ-मूत्र रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया. रिफाइनरी का उद्घाटन राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने किया.
- गाय उत्पादों पर अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण द्वारा भारतीय पारंपरिक प्रणाली के अनुसार दवाओं का उत्पादन किया जायेगा.

महिला दूध बैंक जीवनधारा

- 31 मार्च 2015 को राजस्थान सरकार ने जयपुर में महिला दूध बैंक जीवनधारा की शुरुआत की. इसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र

राठौर ने किया. इसका उद्देश्य राजस्थान में उच्च शिशु मृत्यु दर को रोकना है.

- राज्य सरकार ने इस बैंक का शुभारंभ नार्वे की सरकार और जेके लॉन अस्पताल के साथ मिलकर किया है.
- यह बैंक स्तनपान कराने वाली माताओं द्वारा दान किए गए दूध को जमा करेगा जिसका इस्तेमाल वंचित शिशुओं के लिए किया जा सकेगा. दान देने की इच्छुक माताओं से मिला यह दूध शिशुओं को मुफ्त में दिया जाएगा. दान देने की प्रक्रिया दाताओं की पूरी जांच और एचआईवी, सिफिल्स, हेपेटाइटिस और अन्य बीमारियों की चिकित्सीय जांच के बाद ही शुरु की जाएगी. इसके बाद दूध को पाश्चुरीकृत किया जाएगा जिसमें करीब तीन माह का वक्त लगता है.
- पहला सरकारी महिला दूध बैंक कोलकाता में खोला गया था और जयपुर इस श्रृंखला का दूसरा है. हालांकि राज्य में पहला महिला दूध बैंक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) उदयपुर के एक सरकारी अस्पताल में शुरु किया गया था.
- नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) 2012 के अनुसार राजस्थान में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म पर 49 फीसदी है और इसकी वजह समय पर माता के दूध की अनुपलब्धता है.

देश की पहली जैतून तेल रिफाइनरी

- राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने देश की पहली जैतून तेल की रिफाइनरी का बीकानेर जिले के लूनकरणसर में 3 अक्टूबर 2014 को लोकार्पण किया.
- लूनकरणसर में जैतून तेल की रिफाइनरी की स्थापना के साथ ही राजस्थान ऑलिव ऑयल का उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य हो गया.
- यहां से उत्पादित तेल का ब्रांड नाम 'राज ओलिव आयल' ('Raj Olive Oil') रखा गया है.

अल्पसंख्यक साइबर गांव

- भारत के पहले अल्पसंख्यक साइबर गांव राजस्थान का उद्घाटन अलवर जिले के चन्दौली में 19 फ़रवरी 2014 को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रहमान खान द्वारा किया गया.

साइबर गांव के बारे में

- साइबर गांव परियोजना 15-59 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करेगा.
- आगे भी , परियोजना के तहत अल्पसंख्यक की पर्याप्त आबादी वाले गांवों में स्थापित किया जाएगा.
- इस परियोजना के तहत विशेषज्ञ चन्दौली के लोगों के लिए कम्प्यूटर कौशल का प्रशिक्षण प्रदान करेगें.

ऑनलाइन शॉपिंग होगी 5.5 प्रतिशत तक महंगी

ऑनलाइनशॉपिंग के जरिए मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, रेडिमेड गारमेंट्स, जूते या अन्य कोई भी सामान खरीदना जल्द महंगा होने जा रहा है। क्योंकि सरकार ऑनलाइन शॉपिंग पर 5.5 प्रतिशत का एंट्री टैक्स लगाने जा रही है।

यूरोपियन मंदी की मार राजस्थान तक, करोड़ों का नुकसान:

- यूरोपियन देशों की आर्थिक मंदी का असर प्रदेश के पर्यटन पर भी पड़ा है।
- आंकड़ों के अनुसार 20 वर्षों में विदेशी सैलानियों की तादात में सबसे बड़ी गिरावट वर्ष 2009 में 27 प्रतिशत दर्ज की थी। इसके बाद इन वर्षों में दूसरी गिरावट दिसम्बर 2015 तक दर्ज की गई, जब 3.29 प्रतिशत विदेशियों की आवक 2013-14 की तुलना में कम हुई।
- फिक्की पेपर नॉलेज जारी से ओर की एमआरएसएस -'इंडियन इनबाउंड इंजन ग्रोथ पैक्ड पावर द टैपिंग -' में 'पर्यटन बोर्ड' बनाने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के तहत यह बोर्ड देश में टूरिज्म रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में कार्य करेगा। रिपोर्ट में इनबाउंड पर्यटन के विकास के लिए एक 13 सूत्री रोडमैप का भी सुझाव दिया है।

ढूंढाड़ और ब्रजविकल्प है सर्किट मेवात

- ढूंढाड़ सर्किट में जयपुर हैं। शामिल आभानेरी-दौसा-रामगढ़-सामोद- में रूप के प्वॉइंट विशेष लिए के सैलानियों भी को बावड़ी भांडारेज ।है किया शामिल
- ब्रज रणथम्भौर-करौली-भरतपुर-डीग-सरिस्का-अलवर में सर्किट मेवात- ज से डीग को पावणों वाले आने से ट्रैंगल गोल्डन जरिए केोडने का उद्देश्य है।
- आयोजित में क्षेत्र बांसवाड़ा-डूंगरपुर बाहुल्य आदिवासी में सर्किट बागड़ पैलेस जूना अलावा के मेला बेणेश्वर, शिव मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर को शामिल किया है।

प्रदेश में एक साल में काले हिरण भालू घटे

- वन विभाग की ओर 2015 में कराई गई वन्यजीवों की गणना की हाल ही जारी की गई रिपोर्ट| गणना मई और जून 2015 में की गई थी
- एक साल के भीतर राज्य में काला हिरण,भालू सहित वन्यजीवों की दस प्रजातियों की संख्या घट गई है।
- बघेरा, चीतल, चिंकारा, नीलगाय नौ प्रजातियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
- रिपोर्ट में मुकंदरा हिल, रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व के वन्यजीवों को शामिल नहीं किया है।
- एक साल में बघेरों की संख्या में 14 का इजाफा हुआ है।
- चौसिंघा, चीतल, चिंकारा, जंगली बिल्ली, जंगली सूअर, नीलगाय, सांभर और सेही की संख्या में इजाफा हुआ है।
- भालू, भेड़िया, बिज्जू, हायना, काला हिरण, लंगूर, लोमड़ी, नेवला, सियार और सियागोश की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है।
- वन विभाग की ओर से टाइगर रिजर्व को छोड़कर रिजर्व फारेस्ट और सैंचुरी के क्षेत्र में वाटर होल मेथड से वन्यजीवों की गणना की जाती है। गर्मी में वन्यजीव जब पानी पीने के लिए आते हैं, उस समय यह गणना की जाती है।

सरकारी बिजली कंपनियों के हर सबडिवीजन की अब एनर्जी ऑडिट

- प्रदेशकी तीनों सरकारी बिजली कंपनियों के हर सबडिवीजन की एनर्जी ऑडिट की जाएगी।
- एनर्जी ऑडिट में बिजली की छीजत रेवेन्यू वसूली की पूरी गणना होगी।
- प्रदेश की जयपुर, जोधपुर अजमेर बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय घाटा 90 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। वहीं बिजली छीजत रेवन्यू वसूली नहीं होने के कारण घाटा बढ़ता ही जा रहा है।
- पिछलेसाल एक प्राइवेट कंपनी को एनर्जी ऑडिट का काम दिया था।

थैराकेम रिसर्च मेडीलेब

- सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में इसके लिए थैराकेम रिसर्च मेडीलेब गई की स्थापित इकाई उत्पादन नई की प्रालि (इंडिया)
- पहली बार फार्मा रिसर्च और दवाओं का उत्पादन एक ही छत के नीचे
- बड़े पैमाने पर दवाओं के उत्पादन के लिए फार्मूले को राज्य से बाहर नासिक अंकलेश्वर के प्लांट में भेजा जाता था। लेकिन अब इस नई मैन्युफैक्चरिंग विंग के साथ अब यह उत्पादन राजस्थान में ही किया जा सकेगा जिससे लगभग 100 से अधिक केमिस्ट एक्सपर्ट्स के लिए राज्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे साथ ही इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिलेगा।

यूनिसेफ के अनुसार सबसे ज्यादा बाल विवाह होते है राजस्थान में

- यूनिसेफ के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह।
- देश में 47 फीसदी लड़कियों की शादी 18 की उम्र से पहले हो जाती है।
- यूनिसेफ बाल विवाह विशेषज्ञ डोरा गियूस्टी ने कहा था कि दो दशक में बाल विवाह की संख्या में कमी आई है लेकिन यह कमी प्रतिवर्ष एक फीसदी ही है।
- पूरी तरह से बाल विवाह खत्म करने में करीब 50 साल लगेंगे।
- पूरी देश में सर्वाधिक बाल विवाह राजस्थान में होते हैं
- पिछले पांच साल में प्रदेश में महज 8 हजार बाल विवाह रुकवाए जा सके।
- प्रदेश में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार 16 जिले ऐसे हैं, जहां बाल विवाह काफी संख्या में होते हैं।
- यानी सालाना जितनी शादियां होती हैं, उनमें बाल विवाह का प्रतिशत अन्य जिलों की तुलना में बेहद अधिक है
- जिले जहां सबसे ज्यादा बाल विवाह होते है-राजसमंद, सवाई माधोपुर, टोंक, झालावाड़, दौसा, बूंदी, चित्तौडगढ़, दौसा, अजमेर, करौली, बारां, अलवर, नागौर, उदयपुर और प्रतापगढ़।

युवा उद्यमियों के लिए खुलेंगे 7 इनक्यूबेशन सेंटर

- युवा उद्यमियों को व्यवसाय के लिए तकनीकी ज्ञान और कौशल उपलब्ध करवाने के इनक्यूबेशन सेंटर
- ये सेंटर सभी संभाग मुख्यालयों पर शुरू होंगे।
- सेंटर आईआईएम अहमदाबाद के सेंटर फॉर इनोवेशन इनक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप।जाएंगे किए स्थापित से सहयोग के सीआईआईई)
- ये सेंटर अजमेर में राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय महिला, भरतपुर, झालावाड, बीकानेर, जयपुर के सेन्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेन्स, जोधपुर के एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज तथा सीटीएई उदयपुर मे स्थापित किए जाएंगे

अन्नपूर्णा भंडार

- खाद्यविभाग ने उचित मूल्य की दुकान आवंटन के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार अन्नपूर्णा भंडार खोलने के लिए 200 वर्गफुट दुकान जरूरी है|
- महिलास्वयं सहायता समूहों को नवसृजित उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के संबंध में भी नए निर्देश जारी किए हैं। उचित मूल्य की दुकान आवंटन के लिए महिला स्वयं सहायता समूह का गठन कम से कम 3 वर्ष पूर्व का हो, समूह का कम से कम 3 वर्ष पूर्व बैंक में खाता खुला हो और समूह के सदस्य तीन वर्षों से आंतरिक लेन-देन में संलग्न हों।

बाड़मेर में दुर्लभ खनिज rare earth mineral

- तेल और कोयले के बूते देश की खनिज की आर्थिक राजधानी बन रहे बाड़मेर जिले में एक बड़े खजाने के संकेत मिले हैं|
- यह भारत का पहला टेरिस्टीअल (जमीन पर पाए जाने वाले खनिज) का बड़ा भण्डार है। पूरे विश्व में इसका 97 प्रतिशत निर्यात चीन करता है जबकि तीन प्रतिशत खजाना मलेशिया, अमरीका, आस्ट्रेलिया, ब्राजील और भारत में है।
- बाड़मेर में सिवाना क्षेत्र के कमठाई, दांता, लंगेरा, राखी, फूलन व डण्डाली में यह खजाना है। यहां 745 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टानें हैं। सिवाना के चारों तरफ एक गड्ढेनुमा रचना है, जिसमें ग्रेनाइट और रॉयलाइट व एल्केलाइन आग्नेय चट्टाने हैं। इसे सिवाना रिंग्स कॉम्पलैक्स और मालानी रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है।

15 प्रकार के रेअर अर्थ खनिज

- गैलेनियम, रूबीडियम, इप्रीयम, थोरियम, यूरेनियम, जर्मेनियम, सीरियम, टिलूरियम, यूरेनियम सहित करीब 15 प्रकार के खनिज हैं।

यह है उपयोग

- इन खनिज का उपयोग अंतरिक्ष क्षेत्र, सौर ऊर्जा, सामरिक उपकरण, केमिकल इंडस्ट्री के अलावा अत्याधुनिक तकनीक जैसे सुपर कंडक्टर, हाई प्लग्स, मैग्नेट, इलेक्ट्रोनिक पॉलिसिंग, ऑयल रिफाइनरी में केटिलिस्ट, हाईब्रिड कार कंपोनेंट एवं बैटरी के लिए किया जाता है।

ऊर्जा मित्र सम्मान

- किसको: समयपर बिल जमा करवाने मीटर से छेड़छाड़ नहीं करने वाले उपभोक्ता
- पहला ऊर्जा मित्र सम्मान समारोह सभी जिलों में सात जून को प्रताप जयंती पर होगा
- इस दिन प्रत्येक जिले में 11 आदर्श उपभोक्ताओं को रजत पदक से सम्मानित किया जाएगा
- आदर्श उपभोक्ताओं का चयन उपभोक्ताओं की सूची में से रेण्डम आधार पर 11 आदर्श उपभोक्ताओं का चयन होगा।

डूंगरपुर की फतहगढ़ी पहाड़ी पर भारत माता नमन स्थल

राजस्थान के एक मात्र पर्वतीय पर्यटक स्थल माउंट आबू कीनिक्की झील के किनारे बने भारत माता नमन स्थल की तर्ज पर शहर की फतहगढ़ी पहाड़ी पर भी नमन स्थल बनेगा। इस पर निक्की झील के किनारे बने नमन स्थल पर लगी प्रतिमा की तरह ही चार सिंहों के साथ भारतमाता की करीब 9 से 12 फीट ऊंचाई की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी।

औषधीय पौधा गुग्गुल संकट में

- अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संस्था (IUCN) ने अपनी रेड डेटा लिस्ट में इसको शामिल कर अति दुर्लभ श्रेणी में डाला है।
- इसके विनाश का मुख्य कारण अवैध रूप से इसकी बहुमूल्य गोंद का अति दोहन है।
- अति दोहन एवं धार्मिक कारणों से यह पौधा विलुप्ति की कगार पर पहुंच गया है।
- यहां हैं उपलब्धता: अरावली की पहाडियों में प्रचुरता से उदयपुर, राजसमंद, अलवर (सरिस्का टाइगर रिजर्व), जयपुर (रामगढ़ झालाना क्षेत्र) भीलवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, सिरोही, अजमेर, सीकर, चूरू, झुंझुनूं, पाली आदि।

प्रदेश का तीसरा रोप-वे पुष्कर में

- यह सावित्री माता मंदिर की पहाड़ी पर बना है । इसके अलावा जन्हा रोप-वे है-
- सुंधामाता जालोर - लंबाई 800 मी.
  - मंशापूर्ण करणीमाता उदयपुर - लंबाई 387 मी.
  - जयपुरके सामोद में 350 मी. लंबा रोप-वे बन रहा है।

जयपुर में अल्पसंख्यक ऋण मेले

- अल्पसंख्यकों की शिक्षा, रोजगार ऋण से संबंधी योजनाओं की जानकारी देने और अल्पसंख्यक समुदाय को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करने के लिए
- इनमें केवल योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, बल्कि योजनाओं के लिए आवेदन संबंधी समस्याओं का भी हल किया जाएगा।
- इसके अलावा आयोग प्रदेश भी सभी प्रमुख शिक्षण संस्थाओं के साथ बैठक कर इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की रणनीति भी बनाएगा।
- राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन : जसबीर सिंह

आर्थिक आधार के आंकड़ों के लिए बनी कमेटी

- उप मंत्री मंडलीय समिति के **अध्यक्ष:** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी
- आंकड़ों के लिए बनी कमेटी 120 दिन में अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करगी

देश की पहली डिजीटल पंचायत

- **सीकर जिले कि धोद की ग्राम पंचायत नानी**
- ग्राम पंचायत की छोटी से छोटी सूचना को आप देश के किसी भी कोने में बैठे जान सकते हैं। पंचायत के इतिहास से लेकर जनप्रतिनिधियों की जानकारी, विकास कार्य, सरकारी विभागों से लेकर निजी संस्थाओं तक की जानकारी भी आपको एक क्लिक पर मिल जाएगी।

जोधपुर की पहली देश की दूसरी ग्राम पंचायत दईजर हुई डिजिटल

- पंचायतसमिति दईजर के जितेंद्र फुलवारिया ने अत्याधुनिक मोबाइल एप बनाकर संपूर्ण ग्राम पंचायत दईजर को 'मेक इन इंडिया' 'डिजिटल इंडिया' से जोड़ा
- मंडोर पंचायत समिति संपूर्ण भारत वर्ष में दूसरी डिजिटल पंचायत समिति है जोधपुर की प्रथम समिति

पहला सुपर स्पेशलिटी प्राइवेट पीएचसी

अचरोल में प्रदेश का पहला सुपर स्पेशलिटी प्राइवेट पीएचसी खुला: प्रदेशके पहले 24 घंटे सुपर स्पेशलिटी सेवा देने वाले अचरोल के पब्लिक हेल्थ सेंटर (पीएचसी) उद्घाटन चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने किया। इस पीएचसी को निम्स प्रशासन संचालित करेगा। यहां मरीजों को ओपीडी, एक्सरे समेत उपलब्ध जांचें निशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। सिर्फ दवाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।

आई ट्रैकिंग सिस्टम

अभयारण्यों में बाघों और अन्य वन्य जीवों पर निगाह रखने के लिए आई ट्रैकिंग सिस्टम लगेगा। इनमें असम का कांजीरंगा, उत्तराखंड का कार्बेट और मध्यप्रदेश का रातापानी अभयारण्य शामिल है।

ऑर्गेनिक मंडी

डूंगरपुर- जिले में राज्य की पहली ऑर्गेनिक मंडी: ऑर्गेनिक उत्पाद को बेचने के लिए ऑर्गेनिक प्रॉडक्ट मंडी बनाई जाएगी। ऑर्गेनिक मंडी की का प्रबंधन स्थानीय किसानों की कमेटी करेगी। जो अपने उत्पाद को बेचने का कार्य करेंगी। इन उत्पादों को बेचने के लिए कंपनियां संपर्क में रहेगी।

मंत्रीमंडलीय उपसमिति की बैठक कर्मचारियो की विभिन्न मांगो पर सहमति

- **उपसमिति के अध्यक्ष:** चिकित्सा मंत्रीराजेंद्र राठौड़
- मंत्रालयिक कर्मचारियों का ग्रेड पे 3600करने पर सहमति बनी।
- अनुकंपानियुक्ति के पदों को बढ़ाने और मंत्रालयिक कर्मचारी कैडरके प्रशासनिक अधिकारी के 10000 पदस्वीकृत करने पर भी सहमति बनी।
- मंत्रालयिककर्मचारियों का वेतनमान सचिवालय सेवा के बराबर करने पर भी बैठक में सहमति बनी।

रेडी टू मूव facility राजस्थान सरकार द्वारा

- राजस्थान सरकार इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट बढ़ाने के लिए 'प्लग एंड प्ले' पॉलिसी के तहत जल्द ही रेड टू मूव यानी तैयार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मुहैया कराना शुरू करेगी
- राज्य सरकार इस 'प्लग एंड प्ले' प्लान के तहत इंडस्ट्री को डिवेलप्ड फैसिलिटी मुहैया कराएगी, जहां तुरंत प्रॉडक्शन शुरू किया जा सकेगा।
- इस पॉलिसी के तहत राजस्थान सरकार गारमेंट, जेम्स एंड ज्वैलरी और IT सेक्टर और दूसरे नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री में इनवेस्टमेंट को टारगेट करेगी।
- एसएमई सेक्टर के बहुत से जापानी इनवेस्टर्स ने ऐसी रेडी टू मूव फैसिलिटी लेने में दिलचस्पी दिखाई है।
- सरकारने कंपनियों को खास रियायतें देते हुए तीन श्रेणी के शहरों **जयपुर, जोधपुर और भिवाड़ी** में आवासीय प्रोजेक्ट्स के नियम सरल किए हैं

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना

- राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन एवं राजकीय सेवाओ के लाभ सीधे व पारदर्शी रूप से वितरण हेतु वर्ष 2008 में भामाशाह योजना लागू की गई थी ।
- इस योजना को 15 अगस्त 2014 को वृहद रूप में पुनः संरचित कर प्रारंभ किया गया है ।
- यह योजना, सभी सरकारी योजनाओं के नगद एवं गैर नगद लाभ के सीधे व पारदर्शी रुप से वितरण की देश में पहली योजना है ।
- यह योजना परिवार को आधार मानकर उनके वित्तीय समावेश के लक्ष्य को पूरा करती है, जहाँ हर परिवार को 'भामाशाह कार्ड' दिया जाता है, जो उसके बैंक खाते से जुड़ा होता है ।
- यह बैंक खाता परिवार की **महिला मुखिया** के नाम से होता है और वही इस खाते की राशि को परिवार के हित में उचित उपयोग कर सकती है ।
- यह कार्ड बायो-मैट्रिक पहचान सहित कोर बैंकिंग को सुनिश्चित करता है । इसके अन्तर्गत प्रत्येक परिवार का सत्यापन कर पूरे राज्य का एक समग्र डेटाबेस बनाया जा रहा है । सभी जनसांख्यिकी और सामाजिक मापदण्डों को विभिन्न विभागों द्वारा पात्रता के लिए इसमें सम्मिलित किया गया है

प्रदेशमें 112 नई नगर पालिकाएं:

- 5 हजार से अधिक आबादी की 112 नई अरबन लोकल बॉडी (पालिका) गठित होगी
- प्रदेश में नई नगरपालिकाएं बनने के बाद कुल पालिकाओं और निकायों की संख्या 300 हो जाएगी

क्राइटेरिया

- शहर 5 हजार से अधिक आबादी के हैं,
- 75 फीसदी महिला-पुरुष गैर कृषि कार्य करने वाले होने चाहिए।
- इसके अलावा एक वर्ग किलोमीटर में 400 लोगों की आबादी जरूरी की गई है।
- इस आधार पर राजस्थान में 112 नए शहर पालिका बनने योग्य माने गए हैं।
- केंद्रके नए निर्देश सर्वे के अनुसार सर्वाधिक नई पालिकाएं पश्चिमी बंगाल में 780, केरल में 461, तमिलनाडु में 376, महाराष्ट्र में 279, उत्तरप्रदेश में 267, आंध्रप्रदेश तेलंगाना में 228, झारखंड में 188, गुजरात में 153, कर्नाटक में 126, असम में 126, उड़ीसा में 116 मध्यप्रदेश में 112 बनाई जाएगी।

राज्य में विदेशी पर्यटक

एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में सबसे अधिक फ्रांस के नागरिक शामिल है। पिछले साल राज्य में कुल 1475311 विदेशी पर्यटक आए। इनमें से सबसे अधिक 192727 पर्यटक फ्रांस के थे। इसके बाद यूके यानी इंग्लैंड से आने वाले पर्यटकों की संख्या

125380 थी। तीसरे नंबर पर यूएसए के नागरिक है, चौथे नंबर पर जर्मनी रहा, जहां के 104655 लोग रेगिस्तान और किले को देखने के लिए आए।

स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन , जोधपुर

राजस्थानमें पशुओं के लिए कहां-कहां चारे की पैदावार हो रही है। किस हिस्से में चारे के पैदावार की संभावना है। इसकी पड़ताल करने के लिए स्टेट रिमोट सेंसिंग अप्लीकेशन सेंटर जोधपुर को नया प्रोजेक्ट मिला है, जिस पर स्टेट एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के साथ मिलकर काम करना है

विश्वस्वास्थ्य संगठन (डव्ल्यूएचओ) की जारी प्रदूषित शहरों की सूची में प्रदेश के शहरों की रैंकिंग

- जयपुर और अलवर की रैंकिंग 2014 की तुलना में बढ़ी है।
- जयपुर 41 से 33वें, अलवर 82 से 61वें पायदान पर गया है।
- कोटा, जोधपुर, उदयपुर की रैंकिंग सुधरी है पर प्रदूषण का स्तर बढ़ा है।

बायो टेक्नालॉजी काउंसिल और मिशन

- अध्यक्ष: मुख्यमंत्री
- विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के मंत्री को को-चेयरमैन, किरन मजूमदार को डिप्टी चेयरमैन, मुख्यसचिव, सचिव बायो टेक्नालॉजी, सचिव विज्ञान तकनीकी, स्वाति पी रमल और विल्लु पटेल को सदस्य बनाया गया है
- प्रमुख सचिव विज्ञान एवं तकनीकी को काउंसिल के सदस्य सचिव होंगे।
- इसी तरह स्टेट बायो टेक्नालॉजी मिशन का गठन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा 15 लोगों को शामिल किया गया है।

जोधपुर में पहली सोलर ट्रेन तैयार

जोधपुर वर्कशॉप ने देश की पहली संपूर्ण सोलर ट्रेन तैयार कर ली है। इसमें लाइट-पंखे सौर ऊर्जा से चलेंगे। रेलवे बोर्ड ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत जोधपुर वर्कशॉप को करीब 1.95करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया है। इसके तहत 50 सोलर पैनल वाले कोच बनने हैं। जयपुर में भी ऐसी 22 ट्रेनें तैयार होनी हैं।

न्याय आपके द्वार

- अक्षय तृतीया पर सरकार ने न्याय आपके द्वार कार्यक्रम शुरु किया है
- न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राजस्व लोक अदालत प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर आयोजित किए जाएंगे जिनमें राजस्व सम्बन्धी लम्बित प्रकरणों का मौके पर निस्तारण कराकर लोगों को राहत पहुंचाई जायेगी।
- इसमें किसी प्रकार के सरकारी वकील की जरूरत नहीं होगी।
- इसमें प्री लिटिगेशन की व्यवस्था के साथ ही कोर्ट फीस वकील नहीं रहेंगे।
- अभियान के दौरान नामान्तरकरण, भूमि विभाजन, भू-प्रबन्ध से सम्बन्धित इन्द्राज दुरस्ती, एक ही कुटुम्ब के व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा व निषेधाज्ञा, राज्य सरकार व निजी व्यक्तियों के मध्य विचाराधीन धारा 183(बी) के अन्तर्गत संक्षिप्त विचारण सम्बन्धी, पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान, रास्तों के विवाद सम्बन्धी प्रकरण, इजराय एवं तरमीम सम्बन्धी, स्थाई निषेधाज्ञा सम्बन्धी एवं गैर खातेदारी से खातेदारी तथा अन्य राजस्व सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।

इमरजेंसी नंबर 112

जनवरी से सिंगल इमरजेंसी नंबर 112 एक्टिव हो जाएगा। इसके जरिए पुलिस, फायरब्रिगेड और एंबुलेंस की सुविधा हासिल कर सकेंगे। यह सेवा उन सिम या लैंडलाइन पर भी रहेगी, जिनकी आउटगोइंग सुविधा रोक दी गई है।

दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर

- केंद्र ने 2008 में डीएमआईसी परियोजना लांच की थी।
- इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, गुजरात से होकर महाराष्ट्र तक 1483 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है।
- डीएमआईसी का 39 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान से ही होकर गुजर रहा है।
- यहां डीएमआईसी के पांच चरण होंगे। इसमें कुशखेड़ा- भिवाड़ी-नीमराणा, जयपुर-दौसा, दौसा-राजसमंद-भीलवाड़ा, अजमेर-किशनगढ़ और पाली मारवाड़ शामिल हैं।
- पहले चरण कुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराणा (केबी-एनआर) को विकसित करने के लिए भिवाड़ी इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट अथॉरिटी (बीड़ा) बनाई जाएगी।

मुकुंदरा हिल्स

- हाड़ौती इलाके में
- 2013 में मुकुंदरा हिल्स को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था
- पूर्व में यहां बाघ और बघेरों की उपस्थिति पाई जाती रही है, पर अभी बाघ नहीं है

बिजली कंपनियों में रेस्मा छह महीने बढ़ाया

- सरकारकी ओर से रेस्मा को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है।
- सरकार ने राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 (रेस्मा) के तहत यह पाबंदी लगाई है।
- रेस्मा के दौरान कर्मचारी हड़ताल काम बंद नहीं कर सकेंगे।
- इस दौरान बिजली कंपनियों के ग्रिड सब-स्टेशन (जीएसएस), जनरेटिंग स्टेशन, राजस्थान स्टेट डिस्पैच लोड सेंटर, प्रसारण स्टेशन उसके समस्त कार्यालय उनके कार्यकलापों से संबंधित आवश्यक सेवाओं में हड़ताल नहीं कर सकेंगे। आदेश गृह (आपदा प्रबंध) विभाग ने जारी किया है। गृह (ग्रुप-9) विभाग के संयुक्त सचिव ने बिजली को आवश्यक सेवा घोषित किया है

सेवानिवृत जस्टिस गोपाल लाल गुप्ता

- राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति के अध्यक्ष
- देश में पहली बार वर्ष 2013 में समिति का गठन किया गया था और यह दूसरी समिति होगी।
- अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति तिथि से दो साल का होगा।
- एडवोकेट शशी अग्रवाल, पीएन जलथुरिया एवं शफी मोहम्मद कुरैशी को समिति का सदस्य बनाया गया है।
- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था एनआरके रेड्डी समिति के सदस्य सचिव होंगे।
- **समिति कैसे करेगी काम** : पुलिसअफसरों के खिलाफ शिकायतों की समिति स्वयं भी प्रसंज्ञान लेकर जांच कर सकेगी। जिला स्तर से प्राप्त शिकायतों अथवा कोई पीड़ित व्यक्तिश: उपस्थित होकर या लिखित शिकायत करेगा तो समिति उसकी जांच करेगी। समिति की कार्रवाइयां न्यायिक समझी जाएगी।

शुभलक्ष्मी योजना हुई राजश्री

- मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना का नाम बदलकर एक जून २०१६ से राजश्री
- इसमें लाभान्वित राशि भी 7400 रुपए से बढ़कर 50 हजार रुपए होगी।
- योजना के तहत बालिका के जन्म के समय 2500 रु. की आर्थिक सहायता मां को दी जाएगी।
- दूसरी किस्त पहले जन्मदिन पर 2500 रु. दिए जाएंगे, लेकिन इसमें पूर्ण टीकाकरण होने पर दिया जाएगा।

- पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका की माता के खाते में 4 हजार रु. आएंगे।
- जब बेटी छठी कक्षा में प्रवेश लेगी तो उसकी मां के खाते में 5 हजार रु. और 10वीं में प्रवेश लेने पर 11 हजार रु. सहायता मिलेगी।

जैसलमेर में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण

जैसलमेर जिले के पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायु सेना ने शुक्रवार को सुपर सोनिक बेलस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया।

मेहरानगढ़ दुर्ग को ट्रिप एडवाइजर सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस

- ट्रेवल वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर की ओर से यह प्रमाण पत्र दिया गया है

किले का इतिहास :

- मेहरानगढ़ का भव्य और अद्भुत किला राव जोधा द्वारा 1459 ईस्वी में बनवाया गया था।
- जमीन से करीब 400 फीट की ऊंचाई पर बना ये किला राठौड़ वंश के शौर्य का प्रतीक है।
- राठौड़ वंश के चारण व भाट के अनुसार राठौड़ों का राज पूर्व में तत्कालीन कन्नौज (उत्तरप्रदेश) में हुआ करता था। 12 वीं सदी में मध्ययुगीन राजपूत शासकों की तरह राठौड़ भी अफगानिस्तान के आक्रमणकारियों से हार गए थे। इस दर्दनाक अंत के बाद राठौड़ पाली, मारवाड़ आकर बस गए।
- ऐसा माना जाता है कि राठौड़ वंशजों को यहां ब्राह्मणों को स्थानीय जनजातियों से बचाने के लिए यहां रुकना पड़ा।
- जोधपुर का नाम राव जोधा के नाम पर पड़ा। क्योंकि राठौड़ खुद को सूर्यदेव का वंशज मानते हैं इसलिए किले का नाम रखा गया- मेहरानगढ़, जिसका अर्थ है सूर्य का गढ़। करीब पांच सौ यार्ड लम्बाई में फैले इस दुर्ग की दीवारें 120 फीट ऊंची और 70 फीट मोटी हैं
- इस किले की विशेषता ये है कि जो तत्कालीन राजा जब भी कोई युद्ध जीतते, तो किले में एक नया द्वार बनवाते। इस प्रकार इस किले में सात गेट हैं, जो राजाओं की विजयगाथा गाते हैं। इन द्वारों पर तोप के गोलों के निशान आज भी हैं।
- किले का सबसे बड़ा कमरा मोती महल है, जिसे पर्ल पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। यह महल राजा सूर सिंह ने बनवाया था।

2011 की जनगणना के आधार पर क्षेत्रों का चयन कर सड़कों का आधुनिकीकरण

- यह प्रस्ताव आरआरएसएमपी (राजस्थान रोड सेक्टर आधुनिकीकरण परियोजना) की मध्यावधि (मिडटर्म) समीक्षा बैठक में पीडब्ल्यूडी ने वर्ल्ड बैंक की टीम के सामने रखा।
- आरआरएसएमपी 2014 में शुरू हुई थी, जिसके पहले चरण में 2001 की जनगणना के आधार पर पक्की सड़कें बनाई गईं।
- चूंकि 31 दिसंबर 2018 तक जितनी सड़कों को पक्की करने का काम अंजाम देना था, उसमें से आधे समय में ही 99 प्रतिशत गांवों में पक्की सड़कें बना ली गई हैं। ऐसे में परियोजना का दूसरा चरण जल्द शुरू किया जाएगा

तालछापर में 181 काले हिरण बढ़े

- किस जिले में : चूरू जिले में
- पिछले साल काले हिरणों की संख्या 2492 थी, जो बढ़कर 2673 हो गई है।
- इस बार हुई वन्यजीवों की गणना में तालछापर में चिंकारा 107, नीलगाय 101, जंगली बिल्ली 26, मरू बिल्ली 28, लोमड़ी 78, इंडियन फोक्स 42, बर्ड ऑफ स्प्रे 316, मोर 151, सांडा 8762, जंगली सूअर 35, जैकाल 01 भेड़िया 03 पाए गए।
- यहां सर्दियों में माइग्रेट करने साइबेरिया से कुरजां अन्य विदेशी पक्षी भी आते है।

3033 गांवों में एक भी अपराध नहीं

- प्रदेश के 44,650 गांवों में से क्राइम फ्री 3033 गांवों के लिए सरकार विशेष पैकेज देगी।
- इसके जरिये इन गांवों में आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
- इन गांवों के सरपंच और मुखिया को राजस्थान दिवस पर होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान

- मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का प्रदेश में विधिवत् शुभारंभ 27 जनवरी,2016 को किया गया
- अभियान की कार्य अवधि 4 वर्ष रहेगी । प्रत्येक वर्ष की कार्य योजना में स्वीकृत कार्य उसी वर्ष 30 जून तक पूर्ण किये जाएंगे, प्रथम वर्ष में लगभग 3 हजार 529 गाँवों में जल संग्रहण एवं संरक्षण के कार्य किये जाएंगे। अगले तीन 3 वर्षो में प्रतिवर्ष 6-6 हजार गाँवों को अभियान में शामिल किया जायेगा ।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के सात प्रमुख उद्देश्य

1. राज्य में प्राप्त विभिन्न वित्तीय संसाधनों (केन्द्रीय, राज्य, कॉर्पोरेट जगत, ट्रस्टों, गैर सरकारी संगठन एवं जन सहयोग) का कनवरजेन्स कर जल संरक्षण एवं जल भराव संरचनाओं की गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन करना।
2. ग्रामीणों एवं लाभान्वितों को जल के समुचित उपयोग के बारे में जागृत कर जन सहभागिता से कार्य सम्पादित कराना।
3. ग्राम स्तर पर ग्रामसभा में जल की समग्र आवश्यकता यथा पेयजल, सिंचाई, पशुधन व अन्य व्यवसायिक कार्यो हेतु आंकलन कर उपलब्ध समस्त स्रोतों से प्राप्त जल के अनुरूप जल बजट का निर्माण कर उसी के अनुरूप कार्यों का चिन्हीकरण कर प्रस्ताव पारित कर मिशन की ग्राम कार्य योजना तैयार करना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से प्राप्त जल प्रवाह (वर्षा जल, सतही जल, भू गर्भीय जल एवं मिट्टी की नमी) के जल भराव क्षेत्रों की क्षमता को विकसित करना, जिसमें उपलब्ध जल संग्रहण ढांचो का उपयोंग, अनुपयोगी जल ढांचों का पुनरूद्घार/कायाकल्प कर क्रियाशील करना एवं नये जल संग्रहण ढांचों का निर्माण करना।
5. जल ग्रहण क्षेत्र/कलस्टर/इन्डेक्स कैचमेन्ट को इकाई मानते हुए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कर जल, जंगल, जमीन, जन एवं जानवर का विकास करना।
6. ग्राम को जल आत्म निर्भर बनाकर पेयजल का स्थाई समाधान करना।
7. क्षेत्रों में जल संग्रहण एवं संरक्षण कर सिंचाई क्षेत्रफल को बढ़ाना

मुख्यमंत्रीजल स्वावलंबन अभियान अब गांवों के साथ शहरों में भी चलाया जाएगा।

- क्या होगा इसके तहत : इसके तहत शहरों की आवासीय कालोनियों और सुविधा क्षेत्रों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे।

सार्वजनिक जगहों पर मशीन से सेनेटरी नैपकिन

- ये शुरुआत करने वाला अजमेर पहला जिला
- जनाना अस्पताल में सेनेटरी नैपकिन पैड उपलब्ध कराने के लिए मशीन लगाई गई है।
- इसमें 10 रुपए मूल्य के जितने एक, दो पांच रुपए के सिक्के डालकर नैपकिन प्राप्त किए जा सकेंगे।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान:
- मातृशिशु मृत्युदर में कमी लाने एवं मातृत्व सेवाओं में सुदढ़ीकरण के लिए

- इसके तहत हर माह की 9 June को जिला अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस आयोजित किया जाएगा।
- गर्भवती महिलाओं को डॉक्टरों स्त्रीरोग विशेषज्ञों की देखरेख में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श की निःशुल्क सेवाएं मिलेगी।
- सुरक्षित मातृत्व दिवस अभियान के आयोजन से गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान विशेष रूप से जटिल खतरों वाली संभावित गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबल मिलेगा।

महाराणा प्रताप इंडिया रिजर्व बटालियन

- केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उदयपुर में इंडिया रिजर्व बटालियन की स्थापना की घोषणा की
- इस बटालियन में उन लोगों को स्थान दिया जाए जो पसीना बहाकर जीवन जीने का जज्बा रखते हों।
- केंद्रीय गृहमंत्री ने **जोधपुर की सरदार पटेल पुलिस एकेडमी को काउंटर टेरेरिज्म एकेडमी** बनाने की घोषणा की

विश्व यूनिवर्सिटी तीरंदाजी प्रतियोगिता

- **स्वाति दूधवाल** ने राजस्थान यूनिवर्सिटी को विश्व यूनिवर्सिटी तीरंदाजी प्रतियोगिता में पहला स्वर्ण दिलाया है।
- मंगोलिया के उलानबातर में आयोजित इस प्रतियोगिता में रूस को मात देकर यह पदक पाया

प्रदूषण ज्यादा तो एप भेजेगा चेतावनी

- राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने प्रदेश की सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली इंड्रस्टीज के लिए शनिवार को एक एप लांच किया है।
- एप का नाम: **दृष्टि**
- इस एप की मदद से इंड्रस्टीज मालिक अपने यहां प्रदूषण के आंकड़े जान सकेंगे।
- इंड्रस्टी मालिक एप में अपने इंड्रस्टी को सलेक्ट कर प्रदूषक तत्व की न्यूनतम, अधिकतम और औसत मात्रा का पता लगा सकेंगे।

खिलाड़ियों के लिए 6 जिलों में तैयार किए जाएंगे जिम

- राजस्थानराज्य क्रीड़ा परिषद ने प्रदेश के खिलाड़ियों की फिटनेस के साथ खेल कौशल को निखारने के लिए प्रदेश के 6 जिलों में जिम बनाने की योजना बनाई है।
- क्रीड़ा परिषद ने उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, करौली, अजमेर और जैसलमेर को इसके लिया चयनित किया है

स्टार्टअप्स के लिए रीको और एसबीबीजे के बीच हुआ एमओयू

- राज्य में स्टार्टअप परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (रीको) और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (एसबीबीजे) के बीच एमओयू किया गया
- इस तालमेल से राज्य में इनोवेटिव एंटरप्यूनरषिप को बल मिलेगा और साथ ही नए उद्यमियों को सिंगल विंडो वित्तीय समाधान उपलब्ध हो सकेंगे ताकि वे न्यूनतम समय में अपने कारोबार को स्थापित कर सकें।
- राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी 2015 के तहत सहायता प्राप्त करने के अतिरिक्त अब स्टार्टअप्स, स्टूडेंट्स एंटरप्यूनरस् एवं इन्क्यूबेशन सेंटर्स 'क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्माल एंटरप्राइजेज' (सीजीटीएमएसई) के तहत एक करोड़ रुपए तक का ऋण और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बैंक से 10 लाख रुपए तक का ऋण कोलेटरल मुक्त प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना में अब हर जिले की बीपीएल टॉपर भी शामिल

- 2015 में शुरू की गई मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना| इस योजना में हर जिले की टॉपर रहने वाली दो बेटियों को इस योजना से जोड़ा गया था
- इसमें उसको स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद मिलती है।
- इस योजना में अब दसवीं कक्षा की हर जिले की बीपीएल परिवार की टॉपर बेटी को भी लाभ मिलेगा।
- बीपीएल परिवार की बेटी के इस योजना से जुड़ने से अब हर जिले से 3 बेटियों को यानी राज्य से कुल 99 बेटियों को लाभ मिलेगा।
- योजना में 11 12 की पढ़ाई करते समय किताबें, स्टेशनरी यूनिफार्म के लिए 15 हजार रुपए एकमुश्त सालाना और इन्हीं दो कक्षाओं में खेल कोचिंग, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग की तैयारी छात्रावास शुल्क के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए की मदद का प्रावधान है।
- इससे आगे स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई के लिए स्टेशनरी, किताबें, यूनिफार्म के लिए 25 हजार रुपए एकमुश्त सालाना और कोचिंग, छात्रावास सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए सालाना देने का प्रावधान है।

Extra Fact

- राज्य में चौथा पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) उदयपुर में खुलने वाला है। इससे पहले जोधपुर, सीकर और जयपुर में पासपोर्ट सेवा केंद्र खुले हुए हैं।
- **डूंगरपुर** में कलेक्टर सुरेंद्र कुमार सोलंकी ने जिला प्रशासन की ओर से एक अनाथ बालिका को गोद लेने की घोषणा की है
- **देसू के आनंदसिंह को मिला सर्वश्रेष्ठ पशुपालक सम्मान :** राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह में देसू निवासी आनंदसिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत को पशुपालन क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर जालोर जिले के सर्वश्रेष्ठ पशुपालक पुरस्कार से नवाजा गया
- **'वॉयस ऑफ टोबेको विक्टिम्स' अवार्ड :** तंबाकू नियंत्रण कैंसर पीड़ित परिवारों के लिए उल्लेखनीय कार्य करने पर एसएमएस अस्पताल के कान, नाक गला विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ पवन सिंघल.को दिया
- **सरवन स्मार्ट सिटी सीईओ**
- **अल्पसंख्यकआयोग के अध्यक्ष** जसबीर सिंह
- **युद्धाभ्यास ""चक्रव्यूह-द्वितीय':** भारतीय थल सेना का युद्धाभ्यास , यह हनुमानगढ़ के पल्लू नामक स्थान पर चल रहा है
- **कृषि अनुसंधान केन्द्र बोरवट (बांसवाड़ा)** की ओर से दलहन के 1000 क्विंटल बीज 100 हैक्टेयर जमीन पर बांसवाड़ा में तैयार करवाए जाएंगे। यह पूरा कार्य कृषि अनुसंधान केन्द्र, बोरवट और महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की देखरेख में होगा। वर्ष 2016-17 दलहन वर्ष घोषित किया गया है।
- **अशोक पानगड़िया** SMS मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य न्यूरोलॉजी विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. अशोक पानगड़िया को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है। यह परिषद एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है, जो मंत्रालय के लिए नीति निर्धारण कार्यक्रम तय करती है
- महावीरजी का लक्खी मेला शुरू: महावीरजयंती महोत्सव के अंतर्गत दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी में रविवार को वार्षिक लक्खी मेला स्थापना के साथ शुरू हुआ।

- **मल्लूका मेला**: नृसिंहचतुर्दशी पर जोधपुर में आयोजन
- **राजस्थान मानवाधिकार आयोग: आयोग के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश टाटिया**
- **सपना पूनिया**: राजस्थानकी 20 किलोमीटर रेसवॉक एथलीट
- **राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस :**नवीन सिन्हा
- **एलिस आईलैंड मेडल ऑफ ऑनर अवार्ड :** भारतीयमूल की अमेरिकी चिकित्सक डॉ. रेखा भंडारी को| यह अवार्ड उन्हें बुजुर्गों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में होप कार्यक्रम चलाने पर दिया गया है।
- **सुगम्य भारत अभियान जागरूकता** के प्रथम चरण में जयपुर समेत 48 शहरों को चुना गया है।
- **पीडब्ल्यूडी (PWD)** अकेला ऐसा विभाग है जो हर साल राज्य को नाबार्ड योजना आरआईडीएफ में मिलने वाली 100 प्रतिशत राशि का उपयोग करता है।
- **राजस्थानके तीरंदाज रजत चौहान और स्वाति दुधवाल** का विश्व कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम में चयन हुआ है
- राजस्थान स्मार्ट सिटी प्रस्ताव पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना
- **ऑस्ट्रेलिया रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट-2015 का भागीदार देश**
- राजस्थान सस्ते आवासों हेतु निजी निवेश अपनाने वाला पहला राज्य बना
- कच्छबली गांव राजस्थान का पहला शराब मुक्त गांव बना-राजस्थान के राजसमंद जिले की भीम तहसील में स्थित कच्छबली गांव पहला ऐसा गांव बना जिसमें शराबबंदी के लिए बहुमत में मतदान किया गया.

क्र.	विभाग/पद	पदाधिकारी
1.	अध्यक्ष, अधीनस्थ एंव मंत्रायलिक सेवा चयन सेवा बोर्ड, जयपुर	रामखिलाडी मीणा
2.	अध्यक्ष, मा.शिक्षा बोर्ड. अजमेर	प्रो.बी.एल.चौधरी
3	उपाध्यक्ष, 20 सूत्रीय कार्यक्रम	डॉ दिगम्बर सिंह
4	अध्यक्ष, राज्य सफाई आयोग (नवगठित)	गोपाल पचेरवाल
5	अध्यक्ष, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	मनन चतुर्वेदी
6	चेयरमैन, जे.एम.आर.सी(मैट्रो परियोजना)	अश्विनी भगत
7	अध्यक्ष, जैव विविधता मण्डल, जयपुर	प्रमोद कुमार
8	अध्यक्ष, राजस्व मण्डल,अजमेर	अशोक शेखर
9	मुख्य सूचना आयुक्त	सुरेश चौधरी
10	अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग	प्रकाश टाटिया
11	अध्यक्ष, राजस्थान धरोहर संरक्षण एंव प्रोन्नति प्राधिकरण	ओंकार सिंह लखावत
12	अध्यक्ष, राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण, जयपुर	राजहंस उपाध्याय
13	अध्यक्ष, राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	बालकृषण मीणा
14	अध्यक्ष, राज्य अनुसूचित जाति आयोग	सुंदर लाल
15	अध्यक्ष, राज्य अन्य पिछडा वर्ग आयोग	जितेन्द्र राय गोयल
16	अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग	श्रीमती निशा गुप्ता
17	अध्यक्ष, राज्य अल्पसंख्यक आयोग	सरदार जसबीर सिंह
18	जयपुर अजमेर व जोधपुर डिस्कॉम के चैयरमेन	श्रीमत पाण्डेय
19	राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष	जनार्दन सिंह गहलोत
20	राजस्थान एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष	गोपाल सैनी
21	अध्यक्ष, जन लेखा समिति	प्रद्युम्न सिंह
22	राजस्थान राज्य पुस्तकालय परिषद का अध्यक्ष	वासुदेव देवनानी
23	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति	डॉ सैमपित्रोदा

क्र.	विभाग / पद	प्रथम	वर्तमान
1.	राज्यपाल	सरदार गुरूमुख निहालसिंह	श्री कल्याण सिंह
2.	महिला	श्रीमती प्रतिभा पाटिल	
3.	मुख्य न्यायाधीश	श्री कमलकांत वर्मा	जस्टिस नवीन सिन्हा
4.	मुख्यमंत्री	श्री हरीलालशास्त्री (मनोनीत)	श्रमती वसुंधरा राजे
		श्री टीकाराम पालीवाल (निर्वाचित)	
5.	महिला सांसद	श्रीमती शारदा भार्गव (राज्यसभा)	श्रीमती संतोष अहलावत (लोकसभा)
		महारानी गायत्री देवी (लोकसभा)	
		श्रीमती उषा देवी मीणा (अनुसूचित जनजाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य) श्रीमती सुशीला बंगारू (अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य)	
6.	विधानसभा अध्यक्ष	श्री नरोत्तम लाल जोशी	श्री कैलाश मेघवाल
7.	विघानसभा उपाध्यक्ष	श्री लालसिंह शक्तावत	राव राजेन्द्र सिंह
8.	मुख्य सचिव	श्री के. राधाकृष्णन	श्री ओ.पी.मीणा
9.	महिला मुख्य सचिव	श्रीमती कुशल सिंह	
10.	महानिदेशक पुलिस		श्री मनोज भट्ट
11.	पुलिस कमिश्नर 2011 में सृजित	जयपुर–श्री बी.एल.सोनी	श्री संजय अग्रवाल
12.	अध्यक्ष आर.पी.एस.सी	सर एस.के.घोष	श्री ललित के. पंवार
13.	अध्यक्ष वित्त आयोग	श्री कृष्ण कुमार गोयल	डॉ ज्योति किरण
14.	लोकायुक्त	न्यायमूर्ति श्री आई.डी.दुआ	श्री सज्जनसिंह कोठारी
15.	अध्यक्ष राज्य निर्वाचन आयोग	श्री अमरसिंह राठौड	श्री रामलुभाया
16.	मुख्य चुनाव अधिकारी		श्री गोविन्द शर्मा
17.	राज्य महिला आयोग अध्यक्ष	श्रीमती कांता खतुरिया	सुमन शर्मा
18.	महाधिवक्ता	श्री.जी.सी. कासलीवाल	श्री नरपतमल लोढा

भौगोलिक संकेतक सूची में राजस्थान की वस्तुएँ

भौगोलिक संकेतक	प्रकार
कोटा डोरिया	हस्तशिल्प
ब्लू पोटरी(जयपुर)	हस्तशिल्प
मोलेला क्ले वर्क	हस्तशिल्प
कठपुतली	हस्तशिल्प
सांगानेरी हैण्ड ब्लॉक प्रिंट	हस्तशिल्प
बीकानेरी भुजिया	कृत्रिम
कोटा डारिया लोगो	हस्तशिल्प
फुलकारी	हस्तशिल्प
बगरु हैण्ड ब्लॉक प्रिंट	हस्तशिल्प
थेवा आर्ट वर्क	हस्तशिल्प

मकराना मार्बल(2015)	प्राकृतिक वस्तु

- 13 दिसम्बर, 2015 को शुरू **'भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना'** में लाभान्वित परिवार को 30 हजार रूपए से 3 लाख तक का कवर मिलेगा।
- **ग्राम उदय से भारत उदय अभियान**–14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक
- **चरण पादुका :** जालौर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी द्वारा शुरू किया अनोखा अभियान । यह नंगे पॉव स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए है ।
- **मुख्यमंत्री जन आवास योजना (2015) :** वर्ष 2022 तक सबको मकान उपलब्ध कराने के उध्देश्य से केन्द्र सरकार की और से शुरु की गयी प्रधानमंत्री आवास योजना को प्रदेश में लागू करने के लिए राज्य सरकार ने नीति तैयार की है । योजना के तहत पहले चरण में प्रदेश के 40 शहरो में इसको लागू किया जायेगा।
- **गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना – 2016 :**राज्य में बालिका संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालो को सम्मानित एवं पुरस्कृत करने हेतु "गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना" प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी इस योजना

के तहत प्रत्येक चयनित व्यक्ति को 25 हजार रुपये की नगद राशि पुरस्कार स्वरुप दी जायेगी ।

- **वन धन योजना:** वन क्षेत्र के निकट रहने वाले लोगों के विकास, उनकी वनो की निर्भरता कम करने, रोजगार उपलब्ध करवाने, वन्य जीव तथा वनो की सुरक्षा के लिए **"वन धन योजना"** रणथम्भौर टाइगर रिर्जव, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, माउॅट आबू, कुंभलगढ वन्य जीव अभ्यारण्य एवं जवाई Conservation Reserve में पायलट बेसिस पर लागू की जायेगी।
- **कृष्णा सर्किट :** राज्य में पर्यटन के विकास के लिए कृष्णा सर्किट विकसित किया जाएगा, जिसमें द्वारिका-सांवलियाजी-नाथद्वारा-गोविन्ददेवजी आदि पावन धामों जोडा जाएगा ।
- **औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग** (D.I.P.P.) द्वारा जारी **"ईज ऑफ डूइंग बिजनिस"** के आकलन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व बैंक ने "कारोबार करना आसान" में **राजस्थान को भारत में 6th** स्थान पर रखा गया है । भारत निवेश के लिए सबसे उभरते शहरो में जयपुर को दूसरा स्थान दिया गया है
- राजस्थान में 'प्रदुषण मुक्त उद्योगो' की स्थापना को सुगम बनाने के लिए रीको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र में **"प्लग एण्ड प्ले"** सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।
- **करौली बनेगा हेरिटेज सिटी:** प्राकृतिक सौन्दर्य और पुरासंपदाओं के अलौकिक भंडार को देखते हुए करौली को हेरिटेज सिटी का लुक दिया जाएगा। प्रजेंटेशन में करौली के रावल महल, सुख विलास, गोपाल सिंह जी की छतरी, शहर की ऐतिहासिक इमारतें, दीवारें, द्वार, खिड़कियाँ, शाही कुण्ड, मोती पाल जी का बाग, रणगमॉ ताल, मदनमोहन जी मंदिर, कैला देवी मंदिर, पाँचना डेम, केदारगिरी जी की गुफा जैसे महत्वर्पुण स्थानों के विकास पर चर्चा हुई।
- जैसलमेर में भारत सरकार के सहयोग से गोडावन को संरक्षित करने के लिए ब्रीडिंग सेंटर खोलने की कार्यवाही की जा रही है।
- **जल स्वावलम्बन सप्ताह** -17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक
- BSF की पहली महिला सहायक कमांडेट -तनुश्री पारीक
- राज्य का पहला आइसक्रीम प्लांट-भीलवाड़ा
- प्रदेश का पहला गौ अभ्यारणय -बीकानेर
- देश की सबसे बड़ी मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप (MAST) सोलर वैधशाला-उदयपुर
- **विश्व संगीत उत्सव**-उदयपुर में राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से निजी सहयोग के साथ आयोजित देश का पहला वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल 13 व 14 फरवरी 2016 को फतहसागर की पाल पर हुआ।
- देश का पहला कारपेट पार्क स्थापित होगा-भांडारेज (दौसा)
- मैनकाइंड फार्मा एवं कैडिला कम्पनी प्लांट-कलडवास (उदयपुर)
- वन विभाग मुख्यालय अरण्य भवन का उद्घाटन - जयपुर
- देश का पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित -नोख, जैसलमेर
- प्रदेश का पहला मिनी सुपर मार्केट - थूर गाँव (उदयपुर)
- राज्य का पहला शराब मुक्त गाँव - काछबली (राजसंमद)
- **जीवनधारा :** यह राजस्थान का पहला सरकारी महिला दुग्ध बैंक है ।
- हनुमानगढ में बनेगी प्रदेश की दूसरी बर्ड सेंचुरी - पालीबंगा तहसील के बडोपल गाँव में है ।
- बीकानेर में 25 करोड रुपये की लागत से बीछवाल बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना की घोषणा।
- **राज्य में रुपनगढ (अजमेर) में मेगाफुड पार्क :** किशनगढ के निकट रुपनगढ में मेगाफूड पार्क शुरु किया जा रहा है ।
- **क्रिएटिव सिटी नेटवर्क** - जयपुर व वाराणसी को पहली बार यूनेस्को द्वारा पहली बार "यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क" में शामिल किया गया है ।
- **डिजिटल इंडिया सप्ताह** - बेहतर प्रदर्शन के लिए राजस्थान के तीन जिलो को सम्मानित किया गया - बारॉ, बॉसवाडा, झंझुनू ।
- **राजस्थान उप क्षेत्र योजना :** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्थान उप क्षेत्र योजना को वर्ष (2014-15) लागू किया जायेगा। जिसके तहत अलवर जिले को विकसित किया जायेगा।
- **साउथ ऑस्ट्रेलिया के साथ सिस्टर-स्टेट करार:** इस MOU के तहत दोनो राज्य पेयजल, पर्यावरण, प्रबंधन, ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कृषि व्यापार, खाद्यान, शिक्षा, कौशल विकास और प्रशिक्षण, पर्यटन एंव खेल के क्षेत्रों में व्यापार और निवेश के अवसर तलाशने के लिए साझा कार्य योजना बनाएंगे। आस्ट्रेलिया,रिसर्जेन्ट राजस्थान पार्टनरशिप समिट-2015 का पार्टनर कंट्री था।
- **मलेशिया के साथ 10 हजार करोड़ का MOU :** स्मार्ट-सिटी एवं राजमार्ग एवं शहरी बुनियादी ढाँचे सुदृढीकरण के सत्र में सड़क निर्माण के लिए मलेशिया के साथ 10 हजार करोड़ रुपये का MOU किया ।
- **जापान के साथ MOU :** इस सत्र में 685 करोड़ रूपये राशि 4 MOU पर हस्ताक्षर हुए । ये MOU नीमराणा में ऑटोमोबाइल पार्ट्स, एयर कंडीशर्नस, बेयर हाउस, डिस्ट्रब्यूशन सेंटर एवं फेब्रिकेशन फैक्ट्री एवं फाउंड्री से संबंधित थे ।
- **सिंगापुर के साथ MOU :** ''फोकस क्षेत्र-पर्यटन'' के अन्तर्गत 19 नवम्बर 2015, को CM राजे की उपस्थिति में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और सिंगापुर कॉरपोरेशन इन्टरप्राइजेज के मध्य राज्य के जोधपुर और उदयपुर शहर के आर्किटेक्चर, मास्टर प्लान के संबंध में MOU पर हस्ताक्षर किये गए । सिंगापुर के सहयोग से ITI उदयपुर को सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस	स्थान
हास्पिटेलिटी सेक्टर सिंगापुर द्वारा	उदयपुर
डेगन फूट की खेती के लिए	ढिंढोल,बस्सी (जयपुर)
पिस्ता की खेती के लिए	लूणकरणसर (बीकानेर)
अमरूद उत्कृष्टता केन्द्र	टोंक
खजूर उत्कृष्टता केन्द्र	सगरा भोजका (जैसलमेर)
अनार उत्कृष्टता केन्द्र	बस्सी (जयपुर)
आम उत्कृष्टता केन्द्र	धौलपुर
कैटरपिलर कम्पनी	झालावाड़
केयर्न इंडिया	जोधपुर
संतरा उत्कृष्टता केन्द्र	झालावाड़ एवं नांता कृषि फार्म (कोटा)

युद्धाभ्यास

- **चक्रव्युह** - भारतीय थल सेना युद्धाभ्यास- पल्लू हनुमानगढ में हुआ।
- भारतीय थल सेना का बड़ा युद्धाभ्यास **शत्रुजीत 2016**-महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ। इससे पहले **दृढ संकल्प** नामक योद्धाभ्यास भी हुआ।

- भारत फ्रांस की थल सेनाओं के मध्य तीसरा युद्धाभ्यास **शक्ति 2016** का आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ।
- मार्च 2016 में वायु सेना का अब तक का सबसे बडा युद्धाभ्यास **आयरन फीस्ट 2016** का आयोजन चांधन फील्ड फायरिंग रेंज, जैसलमेर में हुआ।
- नवम्बर 2015 में भारत और रूस की सेनाओं के मध्य **इन्द्र-2015** का आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ।
- राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर सितम्बर से दिसम्बर 2015 तक थलसेना का युद्धाभ्यास-**बाजगति।**
- **सर्वदा विजय अभ्यास :** मथुरा स्थित सेना की स्ट्राइक -1 कोर मे राजस्थान के थार में एक माह लंबा युद्धाभ्यास 3-4 मई, 2014 के मध्य सम्पन्न किया ।

पुरस्कार

- **के.के . बिडला फाउण्डेशन 25वां बिहारी पुरस्कार** - डॉ भगवती लाल व्यास, राजस्थानी कृति ''कठा सू आवे है सबद''
- **महाराणा मेवाड सम्मान** - डॉ लक्ष्मण सिंह राठौड
- **भामाशाह पुरस्कार**-मोहम्मद इमरान, 60 शिक्षण एप बनाये।
- **पहला जगजीत सिंह सम्मान** - इलै राजा
- **सरदार रत्न राष्ट्रीय अवार्ड 2015** - प्रो डी.पी.शर्मा
- **7 वां श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार 2015** - प्रदीप जोशी
- **शिल्पगुरू पुरस्कार**-
  1. कैलाश सोनी -मीनाकारी
  2. रामस्वरूप शर्मा -लकडी पर तारकशी
  3. कैलाश चन्द्र शर्मा - मिनिएचर पेंटिग
- ज्ञानपीठ के 11 वें **नवलेखन पुरस्कार 2015**- ओमनागर ''निब के चीर स''
- **गोयनका राजस्थानी साहित्य पुरस्कार** - सीताराम महर्षि
- राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ नार्थ अमेरिका राना द्वारा चौथा पद्मश्री कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान - पवन पहाडिया
- **अमृता देवी विश्नोई वानिकी पुरस्कार 2015** - जलधारा विकास संस्थान, भीलवाडा
- **राजस्थान रत्न पुरस्कार** - मंजुल भार्गव
- **कृषि कर्मण अवार्ड**-वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्थान द्वारा गेहूं उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि कर्मण अवार्ड प्रदान किया गया। प्रशस्ति पत्र व 2 करोड़ रूपए।
- जालोर के भाखराराम व सवाईमाधोपुर की रामप्यारी को सर्वश्रेष्ठ प्रगतिशील किसान का कृषि मंत्री कृषि कृमण पुरस्कार भी दिया गया। 2 लाख रूपए।
- **बाल साहित्य पुरस्कार, 2015 :** अकादमी में राजस्थानी भाषा के लिए अपने 'धरती रो मोल' बाल कहानी संग्रह के लिए कृष्णा कुमार "आशु" को प्रदान किया गया ।
- **साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, 2015 :** साहित्य अकादमी में 23 भाषाओ में अपने वार्षिक युवा पुरस्कारों की घोषणा की, वर्ष 2015 के लिए कश्मीरी भाषा में कोई पुरस्कार नही दिया गया । राजस्थान की सुश्री ऋतुप्रिया को अपने "अपना संजोवनी हीरान" (कविता संग्रह) के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से परिष्कृत किया गया ।
- **माणक अलंकरण ,2015 :** खोजपूर्ण रचनात्मक पत्रकारिता के लिए दिये जाने प्रतिष्ठित माणक पुरस्कार -2015 और चार विशिष्ट पुरस्कारों की घोषणा 12 दिसम्बर, 2015 को जोधपुर में की गयी
- **माणक अलंकरण** - **MR** जाहिर (जोधपुर)
- सरस डेयरी को इंडिया प्राइड अवार्ड -2015-2016

पदमश्री सम्मान 2016

- गुलाबो सपेरा- लोक नृत्य
- प्रकाश चन्द्र सुराणा-मरणोपरांत, कला एंव संगीत क्षेत्र
- पीयूष पांडे, महाराष्ट्र से नामित - विज्ञानपन एंव संचार
- जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी के प्रथम सी.ई.ओ.वी. सरवन कुमार

खेल - खिलाडी

- **एथलेटिक्स** - समरजीत सिंह , मंजुबाला, घंमडाराम, खेताराम
- **तीरदांज**- रजत चौहान, प्राची सिंह, स्वाति दूधवाल
- **जूडो** - बलविंद्र सिंह
- **रोलबॉल**- रमेश सिंह पाल
- **नौकायन**- शेखरसिंह, सतीश जोशी, हरीश चन्द्र, गिर्राज सिंह, नरेन्द्र सिंह, संदीप कुमार, राकेश रलिया
- **निशानेबाजी**-अपूर्वी चंदेला, ओमप्रकाश , महेन्द्र सिंह रावल, शगुन चौधरी, महावीर सिंह
- **टेबल टेनिस**- विशाखा विजय,
- **हैंडबाल**- मनीषा राठौड
- **कबड्डी**- सुमित्रा शर्मा
- **पोलो**- मेजर रवि राठौड
- **पैरा श्रेणी में** - जगसीर सिंह एथलेटिक्स, संदीप सिंह मान एथलेटिक्स, कमलेश शर्मा-तीरंदाजी, किरण टांक तैराकी
- **पैदल चाल**- सपना 20 किमी
- **भाला फेंक**- देवेंन्द्र झाझाडिया, सुंदर गुर्जर
- **तैराक**- नैकृति, भक्ति शर्मा
- **शतंरज**- अभिजीत गुप्ता
- **डिस्कस थ्रो**- कृष्णा पूनिया
- **स्ट्रैथ पावर लिफ्टिंग विश्व चैम्पयनशिप, 2016** - राजस्थान के पवन कुमावत को दो गोल्ड मेडल
- **बॉलीवाल**- लवमीत कटारिया व दिलीप सोईवाल
- **12 वें दक्षिण एशियाई खेल (सैफ गेम्स)** को आयोजन 5 से 16 फरवरी, 2016 तक गुवाहटी और शिलांग में किया गया। इन खेलों में 8 देशों ने हिस्सा लिया- अफगानिस्तान, बांग्लादेश , भूटान , भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इन 8 देशों के लगभग 3500 खिलाड़ी और खेल अधिकारी पूर्वोत्तर में आयोजित इस सबसे बडे खेल आयोजन में शामिल हुए। भारत ने इन खेलों में कुल 308 पदक जीते । इनमें 188 स्वर्ण पदक, 90 रजत पदक और 30 कांस्य ।
- **निशानेबाजी :** राजस्थान की अपूर्वी चंदेला ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्द्धा में व्यक्तिगत और टीम वर्ग में दो स्वर्ण पदक अपने नाम किए।
- **तीरंदाजी:** राजस्थान रजत चौहान ने पुरुषों की कम्पाउंड स्पर्धा में दो स्वर्ण पदक हांसिल किए।
- **हैमर थ्रो:** राजस्थान के नीरज कुमार ने एथलेटिक्स की हैमर थ्रो स्पर्धा में पाकिस्तान के शकील अहमद को हराकर स्वर्ण पदका जीता।
- **मैराथन दौड़:** पुरूषों की मैराथन दौड़ में राजस्थान के खेताराम ने कांस्य पदक प्राप्त किया।

- **साइकिलिंग:** साइकिलिंग में भारतीय पुरूष टीम में शामिल राजस्थान के मनोहर लाल विश्नोई, अरविन्द कुमार, मंजीत सिंह और दीपक कुमार राही ने प्रथम स्थान प्राप्त किया ।

14 वीं राजस्थान विधानसभा चुनाव (2013)

- विधानसभा की कुल 200 सीटों में से 163 पर एतिहासिक विजय प्राप्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचण्ड बहुमत के आधार पर सरकार का गठन किया, जबकि सत्ता की प्रबल दावेदार कांग्रेस 21 सीटों के साथ बहुत पीछे रह गई।
- इस चुनाव में भाजपा को 163, कांग्रेस कों 21, राजपा को 04 सीटें, बसपा को 3 सीटें, जमीदार पार्टी को 02 सीटें तथा 07 सीटें अन्य उम्मीदवारों की झोली में गई।
- प्रदेश में 4,08,29,288 मतदाता है। राज्य की 14वीं विधानसभा चुनाव के दौरान कुल महिला वोटर 1,91,83,407 में सें 1,44,86,248 ने वोट दिए अर्थात कुल 75.15% मतदान किया।
- 14वी विधानसभा के लिए महिला मतदान पुरूष मतदान से 0.60 प्रतिशत अधिक रहा। इस चुनाव में कुल प्रत्याशियों में 9% महिलाएं मैदान में रही।
- 14वी विधानसभा के चुनाव मैदान में कुल 168 महिला उम्मीदावरों ने अपना भाग्य आजमाया जिनमें से 28 महिलाओं ने जीत दर्ज करवाई जो कुल विधानसभा सीटों का 14% हैं।
- 14 वीं विधानसभा में 28 विजयी महिलाओं में सें भाजपा ने 26 माहिलाओं को टिकिट दिया व 22 जीती।
- कांग्रेस ने 24 माहिलाओं को टिकिट दिया केवल 1 जीती महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने में हमारी विधानसनभा में सबसे ज्यादा महिला हिस्सेदारी : अब तक बिहार नम्बर वन था, हाल ही चुनाव नतीजों से बदली तस्वीर

महिला हिस्सेदारी

- 200 सदस्यीय राजस्थान विधान सभा में –13.5%
- 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में–11.1%
- देश की संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी –11.1% है।
- दुनिया में औसत हिस्सेदारी –22% है।
- महिला विधायक राजस्थान और बिहार में अब 27–27 है।

Special Fact of Rajasthan

- सीधा लाभ हस्तान्तरण (DBT) की शुरूआत करने वाला प्रथम राज्य।
- उद्योग आधार का पंजीयन प्रारंभ करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य।
- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय निर्माण में राजस्थान देशभर में पहले स्थान पर।
- राज्य का सौर विद्युत ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान (1270 मेगावाट)। सौर ऊर्जा की सबसे कम दर प्राप्त।
- सम्पूर्ण राज्य में LED आधारित ऊर्जा दक्ष स्ट्रीट लाइट लगवाने वाला प्रथम प्रदेश।
- ई–मित्र के माध्यम से सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी प्रारंभ करने वाला प्रथम प्रदेश।
- उचित मूल्य दुकानों को ग्रामीण मल्टीब्रान्ड आउटलेट (अन्नपूर्णा) में बदलने वाला प्रथम राज्य।
- परिवाद निस्तारण की एकीकृत ऑनलाइन व्यवस्था करने वाला प्रथम एवं एकमात्र राज्य (राजस्थान सम्पर्क)।
- 61 मुख्य अधिनियम एवं 187 संशोधन अधिनियमों को विलोपित करने वाला पहला राज्य।
- रोजगार सृजन के लिए श्रम कानूनों में महत्वपूर्ण संशोधन करने वाला अग्रणी राज्य।
- **पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना** का क्रियान्वयन करने वाला प्रथम प्रदेश।
- देश में पहली बार किसी राज्य में सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत **दुर्घटना बीमा योजना** में 5 लाख रूपये का बीमा लाभ देने की शुरूआत।
- योजना में प्रीमियम की आधी राशि सहकारी बैंकों द्वारा वहन। अब तक 20 लाख से अधिक किसान पंजीकृत। वर्तमान में फसली ऋण के तहत **दुर्घटना बीमा की देश में यह सबसे बड़ी योजना।**
- जयपुर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेंशनरों के लिए दवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा।
- उदयपुर संभाग में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट विकसित।
- ऊँट को राज्य पशु घोषित।
- काउण्टर मैग्नेट सिटी का उद्देश्य ऐसे शहरी क्षेत्रों का औद्योगिक विकास करना है, जिनके कारण दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में जनसंख्या के पलायन को रोका जा सके। इसके तहत एनसीआर से दूर ऐसे शहरों का चयन किया जाता है, जिनमें एनसीआर की तरह आधारभूत सुविधाएं विकसित करने की संभावनाएं हो।

एसबीसी व ईसीबी आरक्षण विधेयक

एसबीसी को 5 प्रतिशत व आर्थिक रूप से पिछड़ों को 14 प्रतिशत आरक्षण का बिल पास

राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक–2015 और राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिण संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आंरक्षण) विधेयक–2015 विधानसभा में पेश किए।

प्रतिपक्ष के हंगामे के बीच 22 सितम्बर, 2015 को राज्य विधानसभा में चार बिल पास हुए। एसबीसी में शामिल गुर्जरों सहित पांच जातियों को पांच प्रतिशत और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण देने के दो अलग–अलग विधेयक ध्वनिमत से पारित हुए। यह आरक्षण सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों के लिए लागू होगा। इन विधेयकों के पारित होने के साथ ही राज्य में आरंक्षण की व्यवस्था **68 प्रतिशत** तक हो गई है।

राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग को आरक्षण

गुर्जरों के साथ अन्य चार जातियां लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रही थी और लंबे समय से आरक्षण की मांग करने रोकने जैसे प्रदर्शन भी किए गए। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए ही राज्य सरकार यह विधेयक लेकर आई। इस विधेयक के पारित होने के साथ ही इससे पहले पारित अधिनियम 2008 (2009 का अधिनियम संख्या 12) निरसित हो जाएंगे।

एसबीसी में शामिल हैं ये पांच जातियां :

1. बंजारा, बालदिया, लबाना,
2. गाडिया लोहार, गाडोलिया,
3. गूजर, गुर्जर
4. राईका, रैबारी, देवासी
5. गडरिया, गाडरी, गायरी।

आरक्षण कहां मिलेगा : शैक्षिक संस्थाओं और पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों में पांच प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। एसबीसी की जातियों में आने वाले क्रीमीलेयर से संबंधित व्यक्ति नियुक्तियों में आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पद या एकल पद आरक्षण लागू नहीं होगा।

ओबीसी में क्रीमीलेयर की सीमा परिवर्तन-2015

राजस्थान में करीब 2 करोड़ अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आबादी के 30 लाख से अधिक युवाओं के लिए राज्य सरकार ने 16 सितम्बर, 2015 के एक आदेश से ताले लगा दिए है। राजस्थान में 2.5 लाख से अधिक आय वाला ओबीसी श्रेणी का युवा सामान्य वर्ग का माना जाता है। जबकि दूसरे राज्यों में 6 लाख रूपए वार्षिक आय पर ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग का माना जाता है। दूसरी तरफ नेशनल ओबीसी कमिशन ने 15 दिन पहले ही क्रीमीलेयर की सीमा बढ़ा कर 10. 54 लाख रूपए करने की मंत्रालय से सिफारिश की है।

पहले राज्य में 4.5 लाख थी क्रीमी लेयर

पिछली गहलोत सरकार ने पहले 22 दिसम्बर, 2010 को एक आदेश जारी कर क्रीमीलेयर की सीमा 2.5 से 4.5 लाख रूपये की थी लेकिन 17 सितम्बर, 2012 को फिर आदेश कर पूर्व के आदेश को अप्रभावी कर दिया। उसके बाद फिर क्रीमीलेयर की सीमा 2.5 लाख रूपए कर दी। इसमें 2.5 लाख से अधिक आय वाले ओबीसी वर्ग के युवाओं के इसी वित्तीय सीमा के आधार पर ओबीसी या क्रीमीलेयर के प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे है। केन्द्र ने 27 मई, 2013 को आदेश जारी कर क्रीमीलेयर सीमा 4.5 लाख को रिवाइज कर 6 लाख रूपए कर दी थी। इतना ही नहीं इसकी पालना के भी आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि दस साल में क्रीमीलेयर सीमा रिव्यू हो तथा एक बार जिसने आरक्षण का लाभ ले लिया, उसके परिवार की बजाय फिर दूसरे परिवार को आरक्षण मिले।

MAST(मस्त) दूरबीन

विश्व का सबसे बड़ा सोलर टेलीस्कोप मस्त (MAST: Multi Application Solar Telescope) (सौर दूरबीन) उदयपुर की फतेहसागर झील में स्थित 'उदयपुर सौर वैधशाला' में 16 जून, 2015 को लगाया गया है। यह दूरबीन सूर्य के चुम्बकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगी। उदयुपर स्थित इस वैधशाला की स्थापना 1976 ई. में भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन की गयी है। इसके संस्थापक डॉ. अरविन्द भटनागर है तथा यह वैधशाला संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की 'बिग बियर झील' में स्थित वैधशाला के मॉडल के आधार पर विकसित की गयी है।

सौर ऊर्जा में राजस्थान की स्थिति

- सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
- यहाँ सर्वाधिक 1264 मेगावट सौर ऊर्जा उत्पादन हुआ।
- इसके बाद क्रमशः गुजरात (1024 मेगावाट)→मध्यप्रदेश (679)→ तमिलनाडु (419 मेगावाट) हैं।

पिनाक M.K-2

- 28-29 दिसम्बर, 2015 को मल्टी बेरल रॉकेट लांचर पिनाक M.K-2 का पोखरण (जैसलमेर) फील्ड फायरिंग रेंज के चांधन क्षेत्र में सफल परीक्षण किया गया।
- मल्टी बेरल रॉकेट लांचर पिनाक M.K- 2 एक ही बार में 12 रॉकेट छोड़ सकता है और 44 सैकण्ड में दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने की क्षमता रखता है।
- पिनाक M.K-2 DRDO की ओर से निर्मित स्वदेशी रक्षा संयत्र है।

साल्ट ट्यूरिज्म सेंटर

- **दुनिया का पहला साल्ट ट्यूरिज्म सेंटर** सांभर झील में बनाने पर निर्णय लिया गया।
- सांभर लेक एक रामसर साइट है। अतः इसे चुनते हुए **'स्वदेश दर्शन योजना'** में इसके लिए 64 करोड़ रूपये की योजना मंजूर की है।

पासा

- **राज्य के 10 जिलों को पासा की शक्तियाँ :** दिसम्बर 2015 में राज्य सरकार ने ड्रग, शराब एवं भू- माफिया सहित कुख्यात अपराधियों पर कार्यवाही के लिए 10 जिलों को आगामी एक वर्ष तक **राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम- 2006 (पासा)** की शक्तियाँ प्रदान की है। इसके तहत् जिला प्रशासन उस किसी भी दुर्दांत अपराधी को एक वर्ष तक जेल में बंद कर सकता है, जिसकी वजह से लोकशांति भंग होने की आशंका रहती है। जयपुर एवं जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट और अलवर, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर, करौली और दौसा को पासा की शक्तियाँ प्रदान की गई है।

वित्तीय साक्षरता के लिए समझौता

- राज्य में ग्राम स्तर पर वित्तीय साक्षरता और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए दिसम्बर 2015 में नाबार्ड एवं अपेक्स बैंक के मध्य एक MOU पर हस्ताक्षर हुए जिसके तहत् नाबोर्ड इस कार्य के लिए 75 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगा।
- इसी क्रम में राजस्थान देश का प्रथम राज्य बनने जा रहा है जो नाबार्ड के सहयोग से ग्राम स्तर पर लोगो को वित्तीय साक्षरता से बैंको में खाता खुलवाने से लेकर लेनदेन की जानकारी उपलब्ध कराएगा।

प्रत्येक जिले के लिए होगा एक विशेष वन्य जीव

इससे राज्य के प्रत्येक जिलें को एक वन्य जीव के नाम पर एक अलग पहचान मिलेगी और प्रत्येक जिलें की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने जिला स्तरीय वन्यजीव को बचाने एवं संरक्षित करने की दिशा में कार्य करे। राज्य के प्रत्येक जिले के वन्यजीव निम्नलिखित है-

जिला	वन्यजीव
अलवर →	सांभर
बाँसवाड़ा →	जलपीपी

बांरा	→	मगर
भीलवाड़ा	→	मोर
बीकानेर	→	भट्टतीतर
चूरू	→	कालातीतर
धौलपुर	→	पंछीरा
जयपुर	→	चीतल
जैसलमेर	→	गोडावण
जालोर	→	भालू
अजमेर	→	खमनौर
बाड़मेर	→	मरूलोमड़ी
भरतपुर	→	सारस
बूँदी	→	सारस
डूँगरपुर	→	जंगली धोक
हनुमानगढ़	→	छोटा कीकीला
झालावाड़	→	मगरोनी तोता
जोधपुर	→	कुरंजा
कोटा	→	उदबिलाऊ
नागौर	→	राजहंस
राजसमंद	→	भेडिया
श्री गंगानगर	→	चिंकारा
सिरोही	→	जंगली मुर्गी
टोंक	→	हंस
करौली	→	घड़ियाल
पाली	→	तेंदुआ
प्रतापगढ़	→	उड़न गिलहरी
स. माधोपुर	→	बाघ
सीकर	→	शाहीन
उदयपुर	→	बिज्जू

राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कार्पोरेशन

- राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस कार्पोरेशन का होगा पुनर्गठन।
- इसे अब राजस्थान स्टेट पॉवर फाइनेंस एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा।
- उद्देश्य : राज्य के विभिन्न उपक्रमों के पास उपलब्ध आधिशेष राशि बैंको के स्थान पर अब इस कॉपोरेशन के पास सावधि जमा के रूप में रखी जा सकेगी। जिसका उपयोग राज्य के विद्युत कंपनियों तथा अन्य कमजोर यूनिट्स को ऋण देने के रूप में किया जा सकेगा।

राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी

- सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित जयपुर एग्जीबिशन एण्ड कन्वेंशन सेंटर में
- 5 वर्षो में 500 करोड़ का निवेश प्रस्तावित।
- **स्टार्टअप** पॉलिसी लाँच करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य (राजस्थान है)।
- नये बिजनेस आइडिया को प्रोत्साहन देना, बिजनेस आइडिया उद्देश्य मंजूर होने पर 10 लाख रूपए तक का ऋण और एक वर्ष तक 10,000 रूपये भत्ता मिलेगा।

सूफी फेस्टिवल

- जयपुर में सम्पन्न हुआ ''सकि सूफी फेस्टिवल''
- आयोजन ETV News के सहयोग से ''फाउन्डेशन ऑफ सकि राइटर्स एण्ड लिटेचर'' द्वारा किया गया।
- इस सूफी महोत्सव में **8** सार्क देशों-भारत, पाकिस्तान, बाँग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका मालदीव एवं अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान के संगीतज्ञो ने भाग लिया,
- महोत्सव में सूफी नृत्य एवं संगीत कविता, बुक रीड़िग, पुस्तक विमोचन और इंटरेक्टिव का उत्कृष्ट मिश्रण था।

आधारभूत संरचना एंव ढाँचागत विकास

- प्रत्येक ग्राम पंचायत में 0.5 से 2 कि.मी लम्बाई में **c.c** सड़क का निर्माण कर ग्रामीण गौरव पथ के रूप में विकसित करने के प्रथम चरण में 1984 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 1955 की. मी लम्बाई में C.C सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- पूर्व में निर्मित उत्तर-दक्षिण मेगा हाइवे की भाँति **पूर्व-पश्चिम मेगा हाइवे कोरिडोर** विकसित करने के क्रम में पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर योजना के लिए कॉरिडोर चयन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
- इस कॉरिडोर के विकसित होने से -जैसलमेर, नागौर, भरतपुर, धौलपुर, बाड़मेर, जालोर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ व कोटा शहर लाभान्वित होंगे।
- राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण अधिनियम 2015 दिनांक 1.07.15 से लागू हो गया। प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना दिनांक 25.8.2015 को जारी हो चुकी है।

वित्तीय प्रबंधन

- **FRBM ACT** में संशोधनकर राजस्थान विकास एवं गरीबी उन्मूलन निधि पुन: सृजित की गई।
- पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने एवं वर्ष 2015 से 2020 की अवधि के लिए वित्तीय हस्तांतरण के संम्बध में सिफारिश देने के लिए पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया।

कर सुधार

- दिनांक **01-07-2015** से समस्त कर निर्धारण ऑनलाइन किये जा रहे हैं।
- समस्त संभागीय कार्यालयों में पी.पी.पी. मोड में डीलर फैसीलिटेशन सेन्टर ने कार्य करना आरंभ कर दिया है।

NIRMAN FACT FILE

- **नाग का सफल परिक्षण:** 43 किलों वजनी, लागत 300 करोड़, इसमे हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक विस्फोटक काम में लिया गया।, आधुनिक टैंक को भेदने की क्षमता।
- **हाल ही में जो विश्व विद्यालय बंद हुआ:** हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय। इसका स्थानांतरण अब RU में
- **जनजाति विश्वविद्यालय:** बाँसवाड़ा में व इसका नया नाम अब गोविन्द गुरू जनजाति विश्वविद्यालय होगा।
- **विंडमिल पॉवर प्लांट:** केंद्रिय रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने राजस्थान के जैसलमेर के कोडियार गाँव में स्थापित 26 मेगावाट क्षमता का विंडमिल पॉवर प्लाँट राष्ट्र को समर्पित किया।
- **केरोसिन सब्सिडी योजना:** 1 अप्रैल से खाते में केरोसिन सब्सिडी योजना की शुरूआत 8 राज्यों के 26 जिलो से होगी। इनमें राजस्थान से कोटा, पाली, व झुंझुनू शामिल हैं।
- रामसिंह पुरा बना राज्य का **पहला स्मोक-लेस गाँव** (बस्सी तहसील में स्थित)
- **राज्य का पहला सौर ऊर्जा प्लांट:** गुजरात की नर्मदा नदी की तर्ज पर हनुमानगढ़ जिले में मैनावाली माइनर पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर बिजली उत्पादन किया जाएगा। यह देश का दूसरा व राज्य का पहला प्रौजेक्ट होगा।
- **केयर्न इंडिया करेगी राजस्थान ब्लॉक्स में 72 करोड़ डॉलर का निवेश** :निजी क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल

एवं गैस उत्खनन एवं उत्पादक कंपनी केयर्न इंडिया ने उन्नत तकनीक के जरिए, राजस्थान ब्लॉक में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े इन हैंस्ड ऑयल रिकवरी कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा दिसम्बर 2015 में की।

- **झुंझुनू में बनेगा राज्यस्तरीय शौर्य उद्यान:** दिसम्बर, 2015 में राज्य की C.M ने कला एवं संस्कृति विभाग के राज्य स्तरीय शौर्य उद्यान के निर्माण के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान की। यह उद्यान राज्य के जाबांज जवानो और वीरो के शौर्य और पराक्रम को संजोने के लिए झुंझुनू जिले मे बनाया जाएगा।
- **राजस्थान उदय योजना में शामिल:** 7 दिसम्बर, 2015 को राजस्थान सरकार ने केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की UDAY (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) में शामिल करने के लिए अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की।
- **राज्य उच्च शिक्षा परिषद्** का गठन होगा को स्वायत्तशासी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय में क्रमोन्नत करने विश्वविद्यालय में गुणात्मक तथा आधारभूत ढाँचे में सुधार के प्रस्ताव, नीति निधारण तथा क्रियान्वयन का कार्य करेगी।
- **दृढ़ संकल्प:** रेगिस्तान मे 2 माह तक चला थल सेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास।
- **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण** की ओर से 9 नव. 2015 को राज्य के **अजमेर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण** को देश के पाश्चिमी जोन के सर्वश्रेष्ठ विधिक सेवा प्राधिकरण के रूप में सम्मानित किया गया है।
- सीकर में खुलेगा **मल्टी स्किल ट्रेनिंग** सेंटर।
- दक्षिण आस्ट्रेलिया के साथ **सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप समझौता:** रिसर्जेन्ट राजस्थान समित के दौरान सम्पन्न, इसके तहत दोनों राज्य ऊर्जा, पेयजल, पर्यावरण-प्रबंधन, खाद्यान, शिक्षा, कृषि, व्यापार, प्राकृतिक संसाधन, प्रबंधन, कौशल विकास एंव प्रशिक्षण, पर्यटन एवं खेल के क्षेत्र में व्यापार और निवेश के अवसर तलाशने के लिए साझा कार्य योजनाएँ बनाएँगे।
- **जालौर में बनेगा अन्तर्देशीय बंदरगाह :** उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास तथा विनिर्माण गतिविधियो को बढ़ावा देने के लिए जालोर में अन्तर्देशीय बंदरगाह बनाने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत् अरब सागर में मोरी खाड़ी और जालोर के बीच एक नहर बनाई जाएगी।
- हेरीटेज अवॉर्ड से अलंकृत दिल्ली स्थित एतिहासिक पुस्तकालय-''मारवाड़ी सार्वजनिक पुस्तकालय'' ने नव. 2015 में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए।
- दिल्ली जयपुर के मध्य बनेगा **ग्रीन एक्सप्रेस वे:** प्रस्तावित **एक्सप्रेस** हाइवे की लम्बाई 261 कि.मी होगी और यह दिल्ली के इंदिरा गाँधी हवाई अड्डे से शुरू होकर वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर दौलतपुर में समाप्त होगा।
- **हाइवे विलेज :** चित्तौड़गढ़ में बनेगा देश का पहला **हाइवे विलेज**, इन हाइवे विलेज में हेलिपेड, होटल, रेस्टोरेंट जैसी नगरीय सुविधाएँ विकसित की जाएँगी।
- **राजस्थान को सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी राज्य का पुरस्कार:**30 सितम्बर 15 को इंस्टीटयूट ऑफ कम्पिटेटिवनेस एंव प्रतिष्ठित समाचार-पत्र मिंट के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। क्योंकि राजस्थान का भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है।
- **राजस्थान शिक्षक गौरव सम्मान :** इमरान खान को जिन्होने शिक्षा क्षेत्र में उपयोगी और क्रांतिकारी बदलाव हेतु महत्वपूर्ण मोबाइल एप बनाये।
- **माणक अलंकरण:** खोजपूर्ण एवं रचनात्मक पत्रकारिता हेतु जोधपुर के एम. आई. जाहिर को।

चर्चित व्यक्ति

अपूर्वी चंदेला

- 5 जून 16 को 10 मीटर एयर रायफल स्पर्द्धा में 211.2 अंक हासिल कर विश्व रिकार्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता
- 7 जनवरी 16 को 10 मीटर ट्राई सीरीज स्पर्द्धा में 208.9 का स्कोर कर एक स्वर्ण पदक जीता।
- जनवरी 16 में स्वीडन के साहजो में आयोजीत स्वीडिस ग्रां.पी. में उन्हे ''शूटर ऑफ द टूर्नामेंट'' चुना गया।
- अपूर्वी गत वर्ष अप्रेल में कोरिया में आयोजित ISSF विश्व कप में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक कोटा हासिल कर चुकी हैं।

सीमा सिहोरिया व **जगदीश चौधरी** तीरंदाजी खेल से संबधित।

महावीर सिंह - शुटिंग से संबंधित

शकुंत चौधरी - एथलीट (शॉटपुट)

मनन चतुर्वेदी : राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग'' की अध्यक्ष नियुक्त, कार्यकाल 3 वर्ष के लिए (नियुक्ति 6 जनवरी 16), जयपुर स्थित ''सुरमन संस्थान'' की संचालिका है।

रघुवेन्द्र सिंह राठौड़: राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश, दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल (NGT) की मुख्य पीठ में सदस्य नियुक्त 18 जनवरी 2016 को

पंकज पटेल: IIM उदयपुर के चेयरमैन नियुक्त, उद्यमी।

सुंदरलाल: बिलानी भाजपा विधायक ''राज्य अनुसूचित जाति आयोग'' के अध्यक्ष नियुक्त (17 अक्टूबर 15 को)

सुमन शर्मा: राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त (17 अक्टूम्बर 15 को)।

निशा गुप्ता: राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग की अध्यक्ष नियुक्त, 26 अक्टूबर 2015 का।

चंदा जाट : उदयपुर के फलीचड़ा गाँव की बालिका, ताइवान में अन्तर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 6 से 13 अक्टूबर 2015 तक चले कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

इकबाल सिक्का: उदयपुर के शिल्पकार, 465 फीट लम्बे फैक्स रोल पर हस्तलिखित सामाजिक उपन्यास 'अनोखा दहेज' को इंडिया बुक ऑफ रिकार्डस में दर्ज किया गया।

लीना शर्मा व भक्ति शर्मा: उदयपुर की तैराक (माँ-बेटी) इन्होने 2008 में एक साथ इंग्लिश पनैल पार किया।

प्रकाश : 19 अक्टूबर 15 को ''राज्य मानवाधिकार आयोग'' का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

सुरेश चौधरी: Ret.IPS , राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। 19 अक्टूबर 15 को।

चंद्रमोहन मीणा एंव आशुतोष शर्मा: 19 अक्टूम्बर 2015, को Ret. IPS चंद्रमोहन मीना व वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष शर्मा को सूचना आयुक्त नियुक्त किया। जबकि P.S. अग्रवाल पहले से ही सूचना आयुक्त है।

राजस्थान की नवीनतम योजनाएँ एवं कार्यक्रम

बेटी बचाओं. बेटी पढ़ाओ अभियान

- देश में घटते हुए शिशु लिंगानुपात की प्रवृत्ति को देखते हुए 22 जनवरी, 2015 को भारत सरकार द्वारा 'बेटी बचाओं **बेटी पढ़ाओं अभियान**' की शुरूआत की गयी है। यह योजना भारत में असंतुलित शिशु लिंगानुपात वाले 100 जिलों में प्रारम्भ की गयी है।
- इस अभियान में राजस्थान के 10 जिलों-अलवर, **भरतपुर, धौलपुर, दौसा, झुंझुनूँ, सीकर, जयपुर, करौली, सवाईमाधोपुर एवं श्रीगंगानगर** को सम्मिलित किया गया है। राजस्थान में वर्तमान में शिशु-लिंगानुपात 888 है। (जनगणना-2011)

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना

- राजस्थान सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना **13 दिसम्बर 2015** से प्रारम्भ की गई है। इस योजना के तहत लाभार्थी को समस्त सुविधाएँ अन्तरंग (IPD) ईलाज हेतु उपलब्ध होगी तथा कैशलेस होंगी। प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष चिह्नित सामान्य बीमारियों हेतु रू 30 हजार तथा चिह्नित गंभीर बीमारियों हेतु रू 3.00 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जायेगा।
- योजना के तहत चिकित्सा प्रक्रिया से पूर्व 7 दिन तथा छुट्टी पश्चात् के 15 दिन की चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा में कवर होगी।
- हृदय रोग तथा अत्यधिक आघात की स्थिति में 100 से 500 रू तक प्रति परिवार प्रति वर्ष यात्रा भत्ता भी बीमा राशि में शामिल किया गया है।
- योजनान्तर्गत आने वाले लाभार्थी के पास भामाशाह कार्ड होना वांछनीय है। भामाशाह कार्ड ना होने की स्थिति में बीमा लाभ NFSA अथवा RSBY से संबंधित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भी दिया जा सकेगा।
- इस योजना की घोषणा राजस्थान सरकार के बजट 2014-15 की गई थी।
- इस योजना का लाभ भामाशाह कार्ड मिलने के साथ-साथ मिलने लगेगा। इस योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग **67 प्रतिशत** परिवार लाभान्वित हो सकेंगे।

कौशल शक्ति योजना-2014

- इस योजना के तहत हिताधिकारियों (पंजीकृत श्रमिकों) के एक पुत्र/पुत्री को राज्य में संचालित आई.टी.आई. एवं पॉलिटेक्नीक संस्थानों के तकनीकी एवं गैर तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण द्वारा कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सहायता प्रदान की जाती है
- छात्र/छात्राओं को आई.टी.आई/पॉलिटेक्नीक में परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 5-8 हजार रूपये तक प्रतिवर्ष कौशल विकास प्रोत्साहन राशि देय है।
- इस योजना का संचालित राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा किया जा रहा है।

राजस्थान मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

- राज्य सरकार की इस योजना के तहत आगामी 3 वर्षों में राज्य की समस्त कृषि जोतों (खेतों) को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाना है।
- इस योजना का देश में शुभारम्भ प्रधानमंत्री **नरेन्द्र मोदी ने** 19 फरवरी, 2015 को सूरतगढ़ (श्री गंगानगर राजस्थान) से किया गया है। इसके तहत देश के 14 करोड़ किसानों को **मृदा स्वास्थ्य कार्ड'** प्रदान किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान

- राजस्थान की विभिन्न जल संसाधन संबंधी समस्याओं के मददेनजर विभिन्न विभागों के समन्वय से एवं राज्य सरकार द्वारा पृथक से बजट उपलब्ध करवाकर इन समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु **''मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान''** प्रारम्भ किया गया है।
- इस अभियान की अवधि 4 वर्ष रखी गयी है। अभियान के तहत राजस्थान के 21,000 गाँव लाभान्वित होंगे। इसमें गाँवों को चयन करके गतिविधियों का चयन, भूमि के प्रकार एवं उपयोग, ढलान, वर्षा जल की उपलब्धता आदि का आंकलन किया जायेगा एवं इस हेतु योजना, ग्रामवासियों के साथ मिलकर तैयार की जायेगी, इसमें जीआईएस एवं उपग्रह से प्राप्त चित्रों की मदद भी ली जायेगी।

ग्रामीण गौरव पथ योजना

- वर्ष 2014-15 के बजट में घोषित इस योजना के तहत राज्य के जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी **ग्राम पंचायतों** में एक आदर्श सड़क **'ग्रामीण गौरव पथ'** का निर्माण किया जा रहा है।

अल्पसंख्यकों हेतु बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एम.एस.डी.पी.)

- राजस्थान राज्य में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एम.एस.डी. पी) के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल 08 जिलों के 10 ब्लॉक लक्ष्मणगढ़ किशनगढ़बास, रामगढ़, तिजारा (अलवर) नगर, कामां (भरतपुर), चौहटन (बाड़मेर), हनुमानगढ़ (हनुमानगढ़), सम, सांकड़ा (जैसलमेर) एवं तीन कस्बे (मकराना, गंगापुर सिटी एवं टोंक) शामिल किये गये हैं।
- इस योजना के तहत मानसरोवर (जयपुर) में 100 अल्पसंख्यक बालिकाओं के अध्ययन हेतु छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना (MAGPY)

- निर्धारित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में मदद्गार प्रक्रियाओं में तेजी लगाना।
- आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकास और प्रभावी स्थानीय शासन का मॉडल तैयार करना, जिससे कि आसपास की ग्राम पंचायतों को सीखने और इस मॉडल को अपनाने के लिए प्रेरणा मिले।

योजना की पात्रता :-

- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रतिवर्ष एक आदर्श ग्राम पंचायत विकसित की जायेगी।
- चयनित ग्राम पंचायत मैदानी क्षेत्र में 3 से 5 हजार तथा जनजाति व रेगिस्तानी क्षेत्रों में 1 से 3 हजार की आबादी की होनी चाहिए।
- चयनित ग्राम पंचायत विधायक (स्वय/दम्पत्ति) की ग्राम पंचायत नहीं होगी।

श्री योजना (SHREE)

- प्रारम्भ :- वर्ष 2014-15 में राज्य की बजट घोषणानुसार

उददेश्य :-

- श्री योजना (S.H.R.E.E.) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की 5 मूलभूत आवश्यकताओं-

  S- ग्रामीण स्वच्छता, शौचालय निर्माण, तरल एवं ठोस कचरा प्रबंधन

- H-स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता
- R-गॉवों की आन्तरिक सड़के मय नाली निर्माण
- E-शिक्षा एवं चिकित्सा की सुविधाओं का विकास
- E-ग्रामीण क्षेत्र में रोशनी की व्यवस्था को चिह्नित कर सुनियोजित विकास किया जाना है।

पात्रता :-

- श्री योजना अंतर्गत सम्मिलित विभागों द्वारा प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय, 5000 या अधिक आबादी वाले गॉवों में वर्तमान में उपलब्ध 5 मूलभूत आवश्यकताएँ चिह्नित किया जाना है।

लक्ष्य :-

- आगामी 15 वर्ष अर्थात् 2030 ई. तक समस्त ग्रामीण क्षेत्र का सुनियोजित रिकॉर्ड रखा जाना है, जिससे प्रदेश के 43250 गॉवों में आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी।

भामाशाह योजना (ग्रामीण विकास)

- सभी राजकीय योजनाओं के नकद और गैर-नकद लाभ को प्रत्येक लाभार्थी को सीधा पारदर्शी रूप से पहुँचाना।
- राशन कार्ड, पेंशन, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति जैसे लाभार्थियों को भी सम्मिलित नहीं करना।
- मार्च, 2015 तक प्रदेश की सभी महिलाओं का बायोमैट्रिक डाटा सरकार के पास उपलब्ध करवाना।
- योजना की पात्रता :-
- राज्य की पात्र महिलाएँ।
- भामाशाह कार्ड के लिए पंजीकरण कराना जरूरी।
- इस योजना के तहत परिवार प्रमुख महिला सदस्य को बायोमैट्रिक कार्ड जारी किया जाता है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से राज्य में **''सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान''** वर्ष 1999-2000 में केवल 4 जिलों में प्रारम्भ किया गया।
- वर्ष 2005-06 से यह कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है।
- 1 अप्रैल, 2012 से सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का नाम ''निर्मल भारत अभियान'' कर दिया गया।
- 2 अक्टूबर, 2014 से इसे ''स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)'' का नाम दिया गया।

उद्देश्य :-

- इस मिशन का उद्देश्य महात्मा गॉधी की 150वीं जयंती -2 अक्टूबर, 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त करना है।
- माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान द्वारा वर्ष 2017-18 तक राज्य को खुले में शौच से मुक्त बनाने की घोषणा की गई हैं।

प्रावधान :-

- व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (IHHL) इकाइयों के निर्माण एवं उपयोग करने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 12000/- (केन्द्र 75 प्रतिशत यानि रू 9000/- एवं राज्य 25 प्रतिशत यानि रू 3000/-) दिये जाने का प्रावधान है।

पात्रता :-

- सभी बीपीएल परिवार तथा गरीबी रेखा से ऊपर वाले अजा. अजजा लद्यु एवं सीमान्त किसानों, वास भूमि वाले, भूमिहीन श्रमिक, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और महिला मुखिया वाले परिवार पात्र हैं।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना

- प्रारम्भ 13 दिसम्बर, 2015 को CM द्वारा
- लाभ राज्य के 1 करोड परिवारों को, प्रीमियम सरकार देगी।
- योजना हेतु 167 निजी और 250 सरकारी अस्पताल अधिकृत।
- प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष चिन्हित सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए 30 हजार रूपये और चिन्हित गंभीर बीमारियों के लिए 30 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा
- राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA)व राष्ट्रीय बीमा योजना (RSBY) में आने वाले परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा।
- योजना का लाभ भामाशाह कार्ड / राशन कार्ड / RSBY कार्ड से मिलेगा।

भामाशाह रोजगार सृजन योजना

- 13 दिसम्बर 25 से प्रारम्भ।
- उद्देश्य-स्वंय का उद्यम स्थापित कर आत्मनिर्भर बनना।
- इस योजना में बैंको द्वारा प्रदत ऋण पर ब्याज सहायता देय होगी। प्रभावी ब्जाय दर **6 - 7%** होगी।
- इस योजना में 11000 उद्यमों के माध्यम से लगभग 44,000 व्यक्तियों को स्व रोजगार/रोजगार सजृन करने का वार्षिक लक्ष्य रखा गया है।

कौशल विकास

- आरमोल के पुनर्जीवित करने का आधार→ प्रदेश के युवाओं को आजीवीका एवं कौशल विकास के अवसर व्यापक रूप से उपलब्ध कराना।
- राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित कौशल प्रशिक्षण के लक्ष्य प्राप्ति हेतु राजस्थान कौशल एवं आजीवीका विकास निगम (RSLDC) द्वारा निम्नलिखित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहें है:
  - पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
  - नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम
  - कन्वर्जेन्स योजना
  - कौशल विकास पहल योजना
  - कौशल प्रशिक्षण हेतु विशेष योजना

भामाशाह योजना

- **15** अगस्त **2014** से प्रारम्भ
- लैंगिक समानता, वित्तीय समावेश एंव परिवार आधारित लाभों को सम्मलित करते हुए लागू की गई है।
- इसके अन्तर्गत **Direct Benefit Transfer (DBT)** योजना में पेंशन एवं **BPL** खातों में सीधे ही पैसा स्थानान्तरित करने की योजना भी प्रारम्भ की गई है।
- परिवारों को लाभ पहुँचाने हेतु लाभार्थियों के आधार नम्बर, भामाशाह **I.D** एव बैंक खाते इंटरलिंक किये जा रहें हैं।

अपना जिला-अपनी सरकार कार्यक्रम

- आमजन को सुशासन उपलब्ध कराने की दृष्टि से **CM** द्वारा आरभ।
- इसके अन्तर्गत **CM** द्वारा जिलों में जनप्रतिनिधियों से मिलकर स्थानीय समस्याओं का **feedback** लेना, आमजन की समस्या सुनकर उनका निवारण, राजकीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण करके सुधारात्मक कदम उठा रही है।
- सरकार द्वारा जनता से सीधा सम्पर्क स्थापित करने की दिशा में कदम।
- इसमें **CM** व मंत्रीगण व संभागों के गाँव गाँव तक जाकर आमजन की पेशानियाँ सुनते हैं और जहाँ तक संभव हो, उनका त्वरित गति से हल निकालने का प्रयास करते है।

स्मार्ट सिटी मिशन

भारत सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत राज्य के 4 शहरों जयपुर, अजमेर, उदयपुर, एवं कोटा का चयन किया गया।

अमृत परियोजना

भारत सरकार द्वारा जून, 2015 में शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं जैसे नियामित पेयजल की आपूर्ति सीवरेज, पार्क, सार्वजनिक परिवहन की सुव्यवस्था पार्किंग आदि के विकास के लिए अमृत योजना लागू की गई है।

राज्य के 29 शहरों जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी, ब्यावर, हनुमानगढ़, गंगापुर सिटी, हिन्डौन सिटी, सुजानगढ़, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, चूरू, चित्तौड़गढ़, नागौर, बूंदी, भीलवाडा, श्रीगंगानगर, पाली टोंक, झुँझुनू, किशनगढ़, झालावाड में अमृत परियोजना क्रियान्वित की जाएगी।

राजस्थान अमृत योजना के अन्तर्गत

भरतपुर को नगर निगम, डेगाना, किशनगढ़ बास तथा इंटावा को नगरपालिका बनाया गया है,

मुख्यमंत्री हमारी बेटियाँ योजना

यह योजना 'सत्र 2015-16' से प्रारम्भ की गई। जिसमें मेधावी छात्राओं का सम्मान किया जाता है।

कुशल मंगल कार्यक्रम

प्रदेश में हाई रिस्क प्रेगनेन्सी को चिहित कर उनका समूचित प्रबंधन करने के लिए दिनांक 11 जुलाई, 2015 को ''कुशल मंगल कार्यक्रम'' का शुभारम्भ किया गया है।

नई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014

राज्य में 8 अक्टूबर, 2014 से लागू की गई। जिसमे पिछड़े भौगोलिक क्षेत्रों व थ्रस्ट सेक्टर्स में विनियोजन को बढावा देने हेतु विशिष्ट प्रावधान किये जाने की प्रक्रिया तथा कस्टमाईज्ड पैकेज का प्रावधान किया गया है।

निर्माण IAS